लखनऊ

हिंदी दैनिक

# आर्यावर्त क्रांति

बुधवार, 22 अप्रैल, 2026

वर्ष : 11 | अंक: 238

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

"रोज खुद को याद दिलाओ कि तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत और काबिल हो।"

TODAY WEATHER

DAY 28° Hi

NIGHT 17° Low

## 'जो नाम बदलते हैं...': योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश का वार, महुआ मोइत्रा ने भी खोला मोर्चा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**लखनऊ।** टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में एक रैली में एक प्रसिद्ध उद्धरण को गलत तरीके से उद्धृत करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए उन्हें बुलडोजर बुद्धि कहा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बहस में शामिल हो गए और कहा कि केवल उन्हीं लोगों का नाम बदला जाता है जो अपना नाम बदलते हैं। यादव की टिप्पणी आदित्यनाथ के शासनकाल में स्थानों और संस्थानों के नाम बदलने पर एक तीखा प्रहार प्रतीत होती है।

वहीं दूसरी ओर, मोइत्रा ने अपने पोस्ट में आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए लिखा कि हेलो बुलडोजर बुद्धि योगी आदित्यनाथ, अपने तथ्यों को सही करो। नेताजी सुभाष बोस ने कहा था कि मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा'। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा था। कृपया उत्तर प्रदेश में जाकर फैंटा पीते रहो और बंगाल को अकेला छोड़ दो। तुम एक मजाक हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक कथन को गलत तरीके से स्वामी विवेकानंद के नाम से उद्धृत करने का वीडियो टीएमसी के आधिकारिक हैंडल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया गया। वीडियो में लिखा था कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर भाजपा की बंगाल के इतिहास के प्रति घोर अज्ञानता और अवमानना को उजागर किया है। उन्होंने अमर कथन 'मुझे रक्त दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा' स्वामी विवेकानंद के नाम से उद्धृत किया है। जबकि यह कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। X पर पोस्ट में आगे लिखा गया कि दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व। दो बिल्कुल अलग विरासतें। दोनों बंगाल के सपूत। दोनों को एक ही व्यक्ति ने एक ही वाक्य में अपमानित किया। वे स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में अंतर नहीं कर पाते। वे गलत उद्धरण देते हैं। वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माला चढ़ाते हुए उन्हें नेताजी कहते हैं। और फिर भी इन्हीं लोगों में 'सोनार बंगला' बनाने का दुस्साहस है। उनकी अज्ञानता की गहराई उनके अहंकार के बराबर ही है।

## 'किसी भी परिस्थिति में सीलबंद कमरों को नहीं खोला जाए', मतगणना से पहले ईसी ने दिया निर्देश

**नई दिल्ली, एजेंसी।** चुनाव आयोग ने मंगलवार को केरल के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। वह मतगणना के दिन से पहले किसी भी परिस्थिति में कोई भी स्ट्रांग रूम न खोलें।

केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने कोझिकोड के पेरामब्रा निर्वाचन क्षेत्र में सोमवार को ईवीएम रखने वाले एक स्ट्रांग रूम के खोले जाने की खबरों और पलक्कड़ के नेनमारा निर्वाचन क्षेत्र में एक और स्ट्रांग रूम खोलने की कथित योजनाओं के बाद यह निर्देश जारी किया। यह दोहराया गया है कि किसी भी परिस्थिति में इंडेक्स कार्ड तैयार करने या ENCORE पोर्टल में डेटा सत्यापित करने के उद्देश्य से किसी भी मजबूत कमरे या बिना सील वाले कमरे को खोला या उसमें प्रवेश नहीं किया जाएगा। केलकर के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, 'चुनावी प्रक्रिया की अखंडता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।' सोमवार को कोझिकोड जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि कोई भी स्ट्रांग रूम नहीं खोला गया था। कलेक्टर स्नेहल कुमार सिंह, जो जिला चुनाव अधिकारी भी हैं। उन्होंने कहा था कि मतदान अभिलेखों के सत्यापन और अद्यतन के लिए उम्मीदवारों के एजेंटों की उपस्थिति में जेडीटी इस्लाम हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बिना सील वाला सामग्री कक्ष खोला गया था।

## संक्षेप

### नासा के हबल टेलीस्कोप ने कैद की ट्राइफिड नेबुला की शानदार तस्वीर, दिखाई 5 हजार प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड की झलक

नई दिल्ली। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने तारों के निर्माण वाले क्षेत्र ट्राइफिड नेबुला की एक आकर्षक नई तस्वीर जारी की है। यह तस्वीर हबल के लॉन्च की 36वीं वर्षगांठ (24 अप्रैल) के मौके पर सामने आई है। पृथ्वी से करीब 5 हजार प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह नेबुला तारों के बनने और गैस-धूल को आकार देने का अद्भुत नजारा पेश करता है। यह नई तस्वीर न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि यह ब्रह्मांड में हो रही जटिल प्रक्रियाओं को समझने में भी अहम भूमिका निभाती है। हबल का यह मिशन लगातार वैज्ञानिकों को नई जानकारी दे रहा है और अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में मदद कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इस नेबुला में शक्तिशाली तारे अपने आसपास मौजूद गैस और धूल को प्रभावित करते हैं। उनकी तेज हवाएं और ऊर्जा इन बादलों को धकेलती है, जिससे नए तारों का निर्माण होता है। हबल द्वारा ली गई यह तस्वीर इस पूरी प्रक्रिया को बारीकी से दिखाती है, जिससे खगोलविदों को यह समझने में मदद मिलती है कि समय के साथ तारा निर्माण कैसे विकसित होता है। इस तस्वीर में एक अनोखा दृश्य दिखाई देता है, जिसे वैज्ञानिक 'कॉस्मिक सी लेमन' जैसा रूप बताते हैं। यह संरचना गैस और धूल के बादलों से बनी है, जो देखने में किसी समुद्री जीव जैसी लगती है। इसके भीतर कई युवा तारे बन रहे हैं, जिनमें से कुछ अपने आसपास जेट के रूप में ऊर्जा छोड़ रहे हैं।

### 2500 करोड़ का बड़ा साइबर फ्राड, 85 फर्जी खातों का खुलासा; बैंक के तीन अधिकारी समेत 20 गिरफ्तार

**नई दिल्ली, एजेंसी।** गुजरात के राजकोट में 2500 करोड़ रुपये के बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। इस मामले में निजी बैंकों के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। राजकोट (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक विजय गुर्जर के अनुसार, पाधाधरी स्थित यस बैंक के पर्सनल मैनेजर मौलिक कामानी, जामनगर स्थित एक्सिस बैंक के मैनेजर कल्पेश डांगरिया और एचडीएफसी बैंक के पर्सनल बैंकर अनुराग बाल्धा को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि मौलिक कामानी ने पहले से गिरफ्तार आरोपियों की मदद करते हुए संदिग्ध बैंक खाते खुलवाए और उनका संचालन किया। उसने विभिन्न दस्तावेजों का उपयोग कर इन खातों को सक्रिय बनाए रखा, जिससे बड़ी रकम के लेन-देन पर बैंक अलर्ट को नजरअंदाज किया जा सके। वहीं कल्पेश डांगरिया ने फर्जी पहचान के आधार पर खाते खुलवाने में भूमिका निभाई, जबकि अनुराग बाल्धा ने सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया पूरी कर नए खातों को वैध रूप देने में मदद की। तीनों आरोपी खातों से नकदी निकालकर हवाला नेटवर्क के जरिए रकम आगे पहुंचाने में भी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि अब तक इस रैकेट से जुड़े 85 बैंक खातों की पहचान की जा चुकी है और साइबर क्राइम पोर्टल पर 535 शिकायतें दर्ज हुई हैं।

## भारत बना दुनिया का विकास इंजन, वैश्विक संघर्षों के बावजूद तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, यूएन का अनुमान

**नई दिल्ली, एजेंसी।** वैश्विक स्तर पर जारी संघर्षों—जैसे इजरायल-ईरान तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध—के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2026 और 2027 में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रह सकता है।

यूनाइटेड नेशन्स इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक (एस्कैप) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2026 में 6.4 प्रतिशत और 2027 में 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिपोर्ट बताती है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्थाओं ने 2025 में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 2024 के 5.2 प्रतिशत से अधिक है। इसमें भारत की मजबूत आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्ष 2025 में भारत की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत तक पहुंची, जिसे खासतौर पर मजबूत घरेलू मांग—विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों—और कर सुधारों से समर्थन मिला।

हालांकि, 2025 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में कुछ नरमी देखी गई। अमेरिकी टैरिफ नीतियों के कारण भारत के निर्यात पर असर पड़ा और अमेरिका को होने वाले निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बना रहा।

## सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- प्रतिमा छूने की अनुमति नहीं मिलने पर क्या संविधान मदद करेगा?

**नई दिल्ली, एजेंसी।** सुप्रीम कोर्ट में केरल के सबरीमाला मंदिर समेत विभिन्न धर्मों और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ कथित भेदभाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी है। इसके लिए अदालत ने 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया है, जो 2018 के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं पर विचार कर रही है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि यदि किसी आस्थावान भक्त को देवता को छूने से रोका जाता है, तो क्या ऐसे में संविधान उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा? यह टिप्पणी जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने उस समय की, जब यह चर्चा चल रही थी कि जन्म या परंपरा के आधार पर किसी को पूजा-अधिकार से वंचित किया जा सकता है या नहीं।

## 'कभी लौह अयस्क का केंद्र रहा कुल्टी, टीएमसी राज में बंदी की कगार पर'; रैली में शाह की हुंकार

**नई दिल्ली, एजेंसी।** पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तेज हो चुका है और दार्जिलिंग के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी कुल्टी देश में लौह अयस्क उत्पादन का बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण यह क्षेत्र अब बंद होने की कगार पर पहुंच गया है।

अमित शाह ने आरोप लगाया कि राज्य में औद्योगिक विकास की अनदेखी की गई है, जिससे कई पारंपरिक उद्योगों पर संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सही नीतियां अपनाई जातीं, तो कुल्टी जैसे क्षेत्र आज भी देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकते थे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल भाजपा उम्मीदवार को विधायक बनाने या पार्टी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराना है। अमित शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 23 तारीख को कमल के निशान पर वोट दें और चार मई को भाजपा की सरकार बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य में मौजूद हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

### दीदी को हटाने का समय आ गया- दार्जिलिंग की रैली में बोले शाह

दार्जिलिंग आयोजित जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की राजनीतिक स्थिति पर तीखा बयान दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव की मांग अब तेज हो रही है और जनता परिवर्तन की दिशा में सोच रही है। अमित शाह ने गोरखा समुदाय से जुड़े मुद्दों पर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, तो गोरखा बहनों और भाइयों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

## 2000 साल के प्रयोगों के बाद दुनिया थकी, अब भारत की राह देख रही : मोहन भागवत

**अगरतला।** त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने दुनिया की मौजूदा स्थिति और भारत की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया। वे मां सौंदर्य चिन्मयी मंदिर के प्रतिष्ठा और कुंभाभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में पिछले करीब 2000 वर्षों के वैश्विक इतिहास और उसके अनुभवों का जिक्र किया।

अपने भाषण में उन्होंने कहा कि दुनिया ने अलग-अलग व्यवस्थाओं को अपनाकर प्रयोग किए। पहले राजाओं को सारी शक्ति दी गई, लेकिन समय के साथ कई शासक अपनी ही जनता का शोषण करने लगे। इसके बाद लोगों ने ईश्वर को सर्वोच्च मानकर भक्ति आधारित धर्मों को अपनाया, लेकिन शांति की तलाश में शुरू हुए ये रास्ते भी कई बार हिंसा और खून-खराबे में बदल गए।

आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि इसके बाद विज्ञान का दौर आया, जहां लोगों ने यह मानना शुरू किया कि केवल वही सच है जिसे प्रयोगशाला में साबित किया जा सके। इस दौरान विज्ञान ने इंसानों को कई सुख-सुविधाएं दीं, लेकिन असली संतोष आज भी नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि आज भी समाज में दुख, परिवारों का टूटना, अपराध और युद्ध जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जितना विकास हो रहा है, उतना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अपने संबोधन के आखिरी में उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक कई प्रयोगों के बाद अब दुनिया भारत की परंपराओं और ज्ञान की ओर उम्मीद से देख रही है। उनके अनुसार, मानवता को सही दिशा दिखाना भारत की जिम्मेदारी है और यही भारत के अस्तित्व का उद्देश्य भी है।

## 'BJP की विभाजनकारी नीति से जनता को नफरत': तमिलनाडु में केजरीवाल बोले- DMK को हराना मुश्किल, स्टालिन होंगे CM

**चेन्नई।** दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु में डीमके के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर निशाना साधा। आप नेता ने कहा कि कि तमिलनाडु के लोग भाजपा और उसकी विभाजनकारी व कटु राजनीति से नफरत करते हैं, यही वजह है कि पार्टी लंबे समय तक राज्य में अपनी मजबूत पहचान नहीं बना सकी। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा को 27 सीटें मिली हैं और वह AIADMK के साथ गठबंधन में है, लेकिन सभी जानते हैं कि एआईएडीएमके पूरी तरह भाजपा के प्रभाव में है। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर एनडीए को एक भी सीट मिलती है, तो भाजपा बिहार की तरह अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। केजरीवाल ने लोगों से भाजपा, एनडीए और एआईएडीएमके से सावधान रहने की अपील की।

## महिला आरक्षण में देरी पर कांग्रेस का वार, कहा– मोदी सरकार ने परिसीमन का बहाना बनाकर लटकाया मामला

**नई दिल्ली, एजेंसी।** कांग्रेस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे गए पत्रों का हवाला देते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर इसके कार्यान्वयन में देरी करना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी ने 16 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की थी।

रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, 'आठ साल बाद, प्रधानमंत्री इसे परिसीमन से जोड़कर आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी करना चाहते हैं - अभी भी इस मांग पर कदम नहीं उठा रहे हैं।' उन्होंने राहुल गांधी के जिस पत्र का हवाला दिया, उसमें राहुल गांधी ने 2018 में संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए समर्थन का अनुरोध किया था। पत्र में गांधी ने कहा था, 'प्रधानमंत्री महोदय, अपनी कई सार्वजनिक सभाओं में आपने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सार्वजनिक जीवन में अधिक सार्थक रूप से शामिल करने के अपने जुनून के बारे में बात की है। महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए बिना शर्त समर्थन देने की पेशकश से बेहतर महिलाओं के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? और संसद के आगामी सत्र से बेहतर समय क्या हो सकता है? किसी भी तरह की देरी से इसे अगले आम चुनाव से पहले लागू करना असंभव हो जाएगा।' उन्होंने यह भी कहा था, 'हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने के मुद्दे पर, आइए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ खड़े हों और भारत को संदेश दें कि हमारा मानना है कि बदलाव का समय आ गया है। महिलाओं को हमारे राज्य विधानसभाओं और संसद में अपना उचित स्थान लेना चाहिए, जहां वर्तमान में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।'

## ममता बनर्जी के महात्मा गांधी के 'नाइटहुड' दावे पर बीजेपी ने किया फैक्ट चेक, जमकर सुनाया

**कोलकाता, एजेंसी।** पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। बीजेपी ममता सरकार पर जमकर हमलावर है। अब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का एक बयान शेयर करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में नेतृत्व का दावा करने वाले लोगों को सही फैक्ट तक की जानकारी नहीं है।

अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को पोस्ट कर ममता बनर्जी का एक कथित बयान शेयर किया। जिसमें ममता बनर्जी कहती दिख रही थी कि जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। बीजेपी नेता ने कहा, हालांकि इतिहास कुछ और कहता है।

मालवीय ने ममता के बयान का फैक्ट चेक करते हुए बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी अपनी नाइटवुड की उपाधि लौटा दी थी। उन्होंने कहा, तथ्य मायने रखते हैं। खासकर जब पश्चिम बंगाल में नेतृत्व का दावा करने वाले लोग ही बंगाल का सही इतिहास नहीं बता पाते हैं। भाजपा के बयान में कहा गया, 'भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा आंतरिक सर्वे नहीं है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिल रहा जबरदस्त जनसमर्थन टीएमसी को परेशान कर रहा है, इसलिए वह असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की झूठी कहानियां फैला रही है।'

इस बयान को भाजपा के आईटी सेल प्रमुख और बंगाल के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। एक राज्य समिति सदस्य ने बताया कि पिछले कुछ समय से मीडिया में लगातार ऐसे 'काल्पनिक सर्वे' की खबरें सामने आ रही थीं, इसलिए पार्टी ने सोमवार को इस पर आधिकारिक सफाई देना जरूरी समझा।

### टीएमसी पर बीजेपी के आरोप

इससे पहले बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह विधानसभा चुनाव से पहले मीडिया में झूठी और मनगढ़ंत जानकारी फैलाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के नाम पर काल्पनिक आंतरिक सर्वे का हवाला देकर टीएमसी भ्रामक खबरें प्लांट कर रही है, ताकि राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया जा सके। भाजपा ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में साफ किया कि पार्टी ने ऐसा कोई आंतरिक सर्वे नहीं कराया है। पार्टी का आरोप है कि आगामी चुनावों को लेकर बढ़ती घबराहट के कारण टीएमसी इस तरह की गलत जानकारी फैला रही है।

## 'मैं एमजीआर और शिवाजी गणेशन की गोद में खेला, लेकिन'; विजय पर कमल हासन का तंज

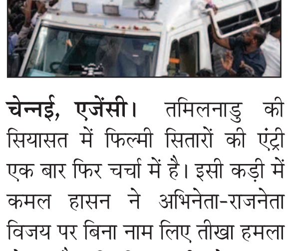

**चेन्नई, एजेंसी।** तमिलनाडु की सियासत में फिल्मी सितारों की एंट्री एक बार फिर चर्चा में है। इसी कड़ी में कमल हासन ने अभिनेता-राजनेता विजय पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला है। तिरुचिरापल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कमल हासन ने कहा कि वह बचपन में दिग्गज नेता और अभिनेता एमजी रामचंजद्रन और महान अभिनेता शिवाजी गणेशन के बेहद करीब रहे, उनकी गोद में तक बैठे, लेकिन कभी इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाया। उनका यह बयान सीधे तौर पर विजय के उस छवि पर निशाना माना जा रहा है, जिसमें उन्हें खुद को एमजीआर का 'उत्तराधिकारी' दिखाने की कोशिश की जा रही है।

कमल हासन ने यह बातें डीएमके उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करते हुए कही। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे डीएमके के चुनाव चिन्ह उगता सूरज को वोट दें। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को अपने इतिहास के बारे में बताया जाना चाहिए, यह समझाना जरूरी है कि यह उगता सूरज किस संघर्ष और विचारधारा से जुड़ा है। उन्होंने विजय के हालिया दौरे पर भी कटाक्ष किया, जहां विजय ने एमजीआर की प्रतिमा के पास फोटो खिंचवाई थी।

# पत्नी और बेटियों के सामने दोस्तों संग घर में ये काम करता था बाप, नौकरानी ने भी बताया बड़ा सच

आर्यावर्त संवाददाता

**कानपुर।** कानपुर में दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने का आरोपी शशिरंजन मिश्रा अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। उसकी पत्नी रेशमा ने उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रेशमा के अनुसार, शशिरंजन शराब और नशीली दवाओं को खाने का लती है। अपने मेडिकल प्रोफेशन के कुछ दोस्तों के साथ उसने कई बार घर पर ही दारू पार्टी की है।

रेशमा ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के कलिम्पोंग की रहने वाली हैं। वर्ष 2010 में नौकरी की तलाश में सहेलियों के साथ शहर आई थीं। स्वरूपनगर स्थित पार्लर में नौकरी करने के दौरान शशिरंजन से मुलाकात हुई थी।

चार साल की दोस्ती के बाद दोनों ने मंदिर में शादी की थी। इसके बाद उन्होंने पार्लर वाली नौकरी छोड़ दी। शशि पहले से शराब पीता था लेकिन लती हो गया था। साथ ही नॉनवेज और दारू पार्टी के लिए दोस्तों को भी घर बुला लेता था। विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता है।

कानपुर के किदवईनगर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में जुड़वां बहनों की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस अधिकारी करीब 15 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। केस को मजबूत बनाने के लिए पुलिस हर पहलू पर साक्ष्य जुटा रही है। इसका उद्देश्य अदालत में आरोपी के खिलाफ पुख्ता आधार प्रस्तुत करना है।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि हत्यारोपी शशिरंजन की पत्नी रेशमा, अपार्टमेंट का सुरक्षा गार्ड प्रेमनारायण दीक्षित और घर में काम करने वाली नौकरानी अमरावती उर्फ आशा इस मामले के प्रमुख गवाह होंगे। तीनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इन्हें केस की कड़ी जोड़ने में अहम माना जा रहा है।

पत्नी के बयान से घरेलू हालात और घटना से पहले की परिस्थितियों पर रोशनी पड़ी है। सुरक्षा गार्ड और नौकरानी ने आरोपी की गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण इनपुट दिए हैं। मौके पर किए गए बेंजीडाइन परीक्षण में हत्यारोपी के हाथ और कपड़ों पर बच्चियों का खून मिला है।

### इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मजबूत आधार

यह उसे सजा दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। नौबस्ता थाना प्रभारी के अनुसार, वारदात वाले कमरे के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जांच का सबसे अहम सबूत हैं। फुटेज के जरिए घटना के समय आरोपी की मौजूदगी, गतिविधियों और घटनाक्रम की समयरेखा को स्पष्ट किया जा रहा है। यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत में आरोपी के खिलाफ मजबूत आधार साबित होगा। आरोपी ने भी वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई अहम तथ्य सामने आए हैं। शुरुआती निष्कर्षों में बच्चियों को पहले नशीला पदार्थ दिए जाने की आशंका जताई गई है।

### ऐसे हुई साजिश की पुष्टि

हत्या में इस्तेमाल किए गए स्टील के चापड़ को आरोपी द्वारा पांच दिन पहले मूलगंज से 500 रुपये में खरीदकर लाने की बात सामने आई है। चापड़ को पहले से खरीदकर लाने से घटना में साजिश की पुष्टि होती है। यह दर्शाता है कि हत्या एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी। पुलिस इस पहलू पर भी गहराई से जांच कर रही है। सभी साक्ष्यों को एक साथ जोड़कर एक मजबूत केस को बनाया जा रहा है।

### जुड़वां बहनों के गले पर चापड़ से हुआ था 12 सेंटीमीटर का घाव

जुड़वां बहनें रिद्धि-सिद्धि की मौत के बाद उनके शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के हाथ भी गले के भाव को देखकर कांप उठे। दोनों मासूमों के गले पर चापड़ रख हथौड़ा मारने के कारण 12 सेंटीमीटर का घाव हो गया था। यह श्वास नली के पास चार सेंटीमीटर लंबा और तीन सेंटीमीटर चौड़ा घाव था। यहीं, डॉक्टरों को शरीर पर कहीं अन्य चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉ विपुल, डॉ महेंद्र ने इस बात से आश्चर्य थे कि आखिर जिन मासूमों ने पहली बार अपने गले से पापा बोला होगा उसी निर्दय पिता ने क्रूरतापूर्वक बड़ी बेरहमी से गले में चापड़ से हथौड़ा मारकर गला काट डाला।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में नशीली दवा खाने की पुष्टि हुई है। जिस कारण शरीर शिथिल पड़ गया और हत्यारोपी पिता हैवान बन गया। इस कारण विसरा भी सुरक्षित किया गया है। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का साफ कहना है कि धारदार हथियार से गला काटने से मौत की पुष्टि हुई है। जांच के लिए कई सैंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

### कानपुर में जुड़वां बेटियों का कत्ल

कानपुर के किदवईनगर के-ब्लॉक स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में शनिवार देर रात पिता शशिरंजन मिश्रा ने अपनी 11 साल की जुड़वां बेटियों रिद्धि-सिद्धि की नृशंस हत्या कर दी। आरोपी ने एक-एक कर दोनों बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी। बचने की गुंजाइश न रहे इसलिए गले पर चापड़ रखकर हथौड़े से वार किए। आरोपी ने वारदात से पहले बच्चियों को नशीली दवा भी खिलाई थी। पूरी वारदात कमरे में लगे सीसीटीवी में कैद है। हत्याकांड के डेढ़ घंटे बाद आरोपी ने तड़के खुद ही पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी।

# सुल्तानपुर को मिला नया डीएम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**सुल्तानपुर।** जिले में मंगलवार को आईएएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने नए जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशासन की प्राथमिकताओं और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। नए जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को जिले में पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने पूर्व जिलाधिकारी कुमार हर्ष से मुलाकात कर उनके द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और उन्हें गति देने का आश्वासन भी दिया। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की वर्तमान स्थिति और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। इंद्रजीत सिंह ने आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पोर्टल और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। साथ ही, राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य संस्कृति में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समय पर कार्यालय पहुंचें और जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी डीएम ने कड़ा रुख अपनाया। आरटीओ, सीडीओ और डीपीआरओ जैसे विभागों में शिकायतों के संबंध में उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला कोषागार में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान सीडीओ विनय कुमार सिंह, एडीएम गौरव शुक्ला, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) राजेश सिंह, सीआरओ बाबूराम, एसडीएम सदर बिपिन द्विवेदी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र सरोज समेत कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

# बुजुर्गों की थाली खाली : एएमयू ने किया अध्ययन, बीमारी-अकेलापन और गरीबी बढ़ा रहे भूख का संकट

आर्यावर्त संवाददाता

**अलीगढ़।** बुजुर्गों की भूख अब सिर्फ रोटी की कमी का सवाल नहीं रह गई है, बल्कि यह बीमारी, अकेलेपन और आर्थिक तंगी का संयुक्त संकट बनती जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन में यह बात सामने आई है कि देश में बड़ी संख्या में बुजुर्ग किसी न किसी स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

फूड एंड ह्यूमैनिटी जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक, करीब 38.2 फीसदी बुजुर्ग हल्की खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं, जबकि 5 फीसदी बुजुर्गों की स्थिति गंभीर है। यह अध्ययन देशभर के 31 हजार से अधिक बुजुर्गों के आंकड़ों पर आधारित है, जो इस समस्या की व्यापकता को बयां कर रहा है। प्रदेश में भी स्थिति अलग नहीं है। अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे कई बुजुर्ग मिलते हैं जो या तो अकेले रह रहे हैं या परिवार के सहयोग से वंचित हैं। ग्रामीण इलाकों में खेती से दूरी और शहरी क्षेत्रों में अकेलापन, दोनों ही हालात भोजन की उपलब्धता को प्रभावित कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश (10.47%) इस सूची में सबसे ऊपर है, जहां हर दस में से एक बुजुर्ग गंभीर भूख की स्थिति में है। इसके बाद झारखंड (8.17%), तमिलनाडु (7.93%), बिहार (7.88%) और पश्चिम बंगाल (7.55%) का स्थान है। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 7.13% है। इन राज्यों में राष्ट्रीय औसत 5.14 प्रतिशत से काफी अधिक बुजुर्ग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय असमानताओं और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को उजागर करता है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि मुस्लिम और ईसाई समुदायों के बुजुर्गों में खाद्य असुरक्षा का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि हिंदू और सिख समुदायों में स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर पाई गई। भूगोल विभाग के शोधकर्ताओं का कहना है कि हर पांच में से एक बुजुर्ग किसी न किसी स्तर पर भोजन की असुरक्षा से जूझ रहा है। सरकारी योजनाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड मौजूद हैं, लेकिन कई बुजुर्गों तक लाभ समय पर नहीं पहुंचता। इसमें पहचान और पंजीकरण की दिक्कत के अलावा पोषण पर खास फोकस की कमी देखी जा रही है। अगर समय रहते स्थानीय स्तर पर पहचान और मदद की व्यवस्था मजबूत नहीं हुई, तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और गहरी हो सकती है।

### बीमारी के साथ भूख की दोहरी मार

एक तरफ गांवों में बुजुर्ग खेती से अलग हो रहे हैं और दूसरी ओर शहरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के सामने भोजन की समस्या पैदा हो रही है। इनमें से अगर बीमार बुजुर्गों की बात करें तो बीमार और चलने-फिरने में असमर्थ लोगों की स्थिति सबसे खराब है। शोधकर्ता सैयद नौशाद अहमद और मो मोहसिन ने अध्ययन में बताया कि कई बुजुर्ग दवाइयों और इलाज पर खर्च के कारण भोजन पर कटौती कर देते हैं। इसका नतीजा है कि बुजुर्गों में कमजोरी बढ़ रही है। बीमारियां और गंभीर होती जा रही हैं और काम करने की क्षमता खत्म हो रही है।

### सिर्फ गरीबी नहीं, कई कारण जिम्मेदार

शोध में सामने आया है कि बुजुर्गों में भूख का संबंध केवल आय से नहीं है। खराब स्वास्थ्य और चलने-फिरने में दिक्कत, मानसिक अवसाद और अकेलापन, परिवार से दूरी या सहारा न होना, सामाजिक और आर्थिक असमानता जैसे कारक मिलकर बुजुर्गों को भोजन से वंचित कर रहे हैं।

# विधायक के कथित बयान से समाजवादियों में रोष

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**सुल्तानपुर।** परशुराम जयंती कार्यक्रम में दिए गए कथित बयान को लेकर जिले की राजनीति गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सीओ सदर सौरभ सामंत को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शहजाद व अधिवक्ता अशोक विसेन के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कादीपुर के भाजपा विधायक राजेश गौतम के बयान से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। मंच से एक विशेष समुदाय के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए सपाइयों ने कहा कि इससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन रहा है।सपाइयों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में शहजाद अहमद, अशोक सिंह बिसेन, पवन यादव, राजदेव निषाद, ज़रताब रज़ा सुल्तान खान मोनू, सुरेश कुमार गौतम, अल्ताफ अहमद शानू, राकेश वर्मा, नदीम सिद्दीकी, सुभाष यादव, शाकिम अब्बास, सत्यम पाण्डेय, सईद अहमद, महफूज अहमद, सुग्रीव निषाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

# घर में जमा कर रखा था बारूद, भीषण गर्मी से अचानक हुआ जोरदार धमाका... 15 साल की लड़की की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

**सम्भल।** उत्तर प्रदेश के सम्भल जिले से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक घर में रखे अवैध पटाखों के जखीरे में भीषण विस्फोट हो गया। इस धमाके ने न केवल एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं, बल्कि पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। भीषण गर्मी के बीच बारूद के इस विस्फोट में एक 15 वर्षीय किशोरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दूसरी लड़की और घर का मालिक गंभीर रूप से घायल हो गए।

मामला रजपुरा थाना क्षेत्र के ईसाकपुर गांव का है। यहाँ एक आतिशबाज का पटाखा बनाने का लाइसेंस काफी समय पहले खत्म हो चुका था। इसके बावजूद, नियमों को ताक पर रखकर घर के भीतर भारी मात्रा में अवैध पटाखों और बारूद का भंडारण किया गया था।बताया जा रहा है कि आसमान से बरसती आग और भीषण गर्मी के कारण बारूद ने अचानक विकराल रूप ले लिया और एक जोरदार धमाका हुआ।

### धमाके से दहल उठा गांव, मची चीख-पुकार

धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा गांव दहल उठा और घर की दीवारें ढह गईं। इस हादसे की चपेट में आतिशबाज की दो पौत्रियां आ गईं। 15 साल की किशोरी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी किशोरी और स्वयं आतिशबाज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाके के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चारों तरफ धुआं और चीख-पुकार सुनाई देने लगी।

### प्रशासनिक कार्रवाई और जांच

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से नमूने एकत्र किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि प्रशासन की नाक के नीचे रिहायशी इलाके में इतना बड़ा अवैध जखीरा कैसे जमा था? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

# आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरित पुष्टाहार में कीड़े मिलने की शिकायत

आर्यावर्त संवाददाता

**लंभुआ/सुल्तानपुर।** लंभुआ विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मकसूदन स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से वितरित किए गए पुष्टाहार में कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई है। शिकायत की पुष्टि होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने पुष्टाहार को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है।

लाभार्थी एवं भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद के राष्ट्रीय सचिव धीरेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर से दूरभाष पर शिकायत दर्ज कराई थी कि केंद्र से वितरित दाल एवं दलिया में कीड़े पाए गए हैं। शिकायत पर सीडीपीओ प्रवीण कुमार विश्वकर्मा एवं डीपीओ शरद त्रिपाठी ने आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर जांच की। जांच में शिकायत की पुष्टि हुई। डीपीओ ने केंद्र पर उपलब्ध पुष्टाहार को अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया। डीपीओ शरद त्रिपाठी ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि गुणवत्ता विहीन पुष्टाहार का वितरण नहीं होने दिया जाएगा।वहीं श्री सिंह ने बताया कि उनके एवं संगठन के पदाधिकारी जिला सचिव कृष्ण कुमार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सनी सिंह, सदस्य जमाल अहमद द्वारा कई ग्राम पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की गई और पुष्टाहार में खामियां पाई गईं।

# 'जांच' या औपचारिकता! अवैध निर्माण पर शिकायत के बाद बनी कमेटी पर उठे सवाल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**सुल्तानपुर।** शहर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और बढ़ते जाम के खिलाफ उठी आवाज अब प्रशासनिक जांच तक पहुंच गई है, लेकिन इस जांच की निष्पक्षता पर शुरुआत से ही सवाल खड़े होने लगे हैं। अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता रविन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सौंपे गए शिकायती पत्र पर एडीएम (एफआर) राकेश सिंह ने संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी का गठन किया है, मगर इस कमेटी की संरचना ही चर्चा का विषय बन गई है।

शिकायत में साफ आरोप है कि शहर के कई इलाकों में बिना मानचित्र स्वीकृति, बिना पार्किंग और नियमों को ताक पर रखकर बहुमंजिला इमारतें और कॉम्प्लेक्स खड़े किए जा रहे हैं। नतीजा- संकरी होती सड़कें, रोज का जाम और बढ़ते हादसे। गोलाघाट से लेकर चौक घंटाघर, लखनऊ रोड से लेकर सीताकुंड तक, संदिग्ध निर्माणों की लंबी फेहरिस्त प्रशासन को सौंपी गई है।

लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है जिस व्यवस्था पर मिलीभगत का आरोप है, उसी व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को जांच की कमान सौंप दी गई है। जांच कमेटी में अपर उपजिलाधिकारी सदर करन सिंह, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लालचंद्र सरोज और नगर कोतवाल संदीप राय को शामिल किया गया है। अब सवाल यही है कि जिन पर शहर में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं, वही अब जांच की कुर्सी पर बैठकर सच तलाशेंगे। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि क्या यह जांच महज औपचारिकता बनकर रह जाएगी? क्योंकि शिकायत में यह भी आरोप है कि विनियमित क्षेत्र कार्यालय अक्सर नोटिस जारी कर मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देता है, जबकि निर्माण कार्य जारी रहता है।

पार्किंग विहीन कॉम्प्लेक्स, सड़क किनारे खड़े वाहन और अतिक्रमण से जूझता शहर पूछ रहा है क्या इस बार सच में कार्रवाई होगी, या फिर फाइलों में ही सिमट जाएगी पूरी कवायद? अधिवक्ता की मांग है कि पिछले दस वर्षों में हुए सभी निर्माण कार्यों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए और दोषियों पर एफआईआर दर्ज हो। लेकिन जिस तरह की कमेटी बनाई गई है, उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा संदेह के घेरे में ला दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुलतानपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई वास्तव में बदलाव लाती है या फिर यह भी सिस्टम की एक और रूटीन प्रक्रिया बनकर रह जाती है।

### यातायात व्यवस्था में सहयोगी बने रोवर्स रेंजर्स कैडेट्स

**सुल्तानपुर।** राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रोवर्स रेंजर्स कैडेट्स यातायात पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था सुधारने में लगातार सहयोग दे रहे हैं। यह जानकारी देते हुए महाविद्यालय की रेंजर प्रभारी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ वीना सिंह ने बताया कि जनपद मुख्यालय की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पिछले हफ्ते से ही राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय की रोवर्स रेंजर्स टीम ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम निरंजन के निर्देशन में लगातार काम कर रही है। रोवर्स रेंजर्स कैडेट्स ने हेलमेट जागरूकता रैली, सड़क सुरक्षा अभियान व विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक नियम पालन हेतु जागरूकता अभियान से जुड़कर लोगों को सुरक्षित और अनुशासित यात्रा के लिए प्रेरित किया है। रोवर्स प्रभारी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान में रोवर्स रेंजर्स टीम का नेतृत्व मीना मौर्या कर रही हैं।

# थप्पड़, लात-घूंसे... बिन बुलाए शादी में पहुंचा युवक तो लोगों ने पीट-पीटकर किया अधमरा

आर्यावर्त संवाददाता

**औरैया।** उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में खुशियों से भरा एक शादी समारोह उस वक्त दहशत में बदल गया, जब बिना निमंत्रण पहुंचे एक युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर अधमरा कर डाला। मामला अब सवालों के घेरे में है। क्या बिना बुलाए शादी में पहुंचना इतनी बड़ी गलती है कि किसी की जान खतरे में पड़ जाए?

पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर रोड स्थित हरलाल धाम गेस्ट हाउस का है, जहां एक शादी समारोह चल रहा था। रंग-बिरंगी रोशनी, बजते बैंड-बाजे और मेहमानों की चहल-पहल के बीच हर कोई जश्न में डूबा हुआ था।

इसी दौरान एक युवक चुपचाप शादी में पहुंचा और खाना खाने लगा। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों को जब शक हुआ कि वह बिना निमंत्रण के आया है, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया।

पहले उससे सामान्य पूछताछ की गई कि कहां से आए हो, किसके बुलावे पर आए हो? लेकिन युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बस यहीं से माहौल बदल गया।

देखते ही देखते कुछ लोग गुस्से में आ गए और बात कहासुनी से आगे बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई। युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा गया। थप्पड़, लात-घूंसे बरसाए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। शादी की खुशियों के बीच अचानक चीख-पुकार गूंजने लगी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को एंबुलेंस से 50 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया।क्राइम इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि युवक गेस्ट हाउस में खाना खाने के लिए गया था। वहां मौजूद लोगों ने उससे पूछताछ की, लेकिन सही जवाब न मिलने पर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी।

युवक ने पूछताछ में बताया कि उसने पछैया से कच्ची शराब पी रखी थी। फिलहाल पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भूख मिटाने की कोशिश इतनी बड़ी गलती है कि किसी को इस तरह पीट-पीटकर अधमरा कर दिया जाए?

फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन घटना ने समाज की संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी।

नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर समर्थन न देने वालों के खिलाफ देशभर में आक्रोश

# ‘महिलाओं की भागीदारी प्रधानमंत्री की नीतियों में विश्वास का प्रतीक’

**आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो**

**लखनऊ।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चेहरा अलोकतांत्रिक है तथा इनके कृत्य महिला विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, जिस पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दलों द्वारा इस विधेयक का समर्थन नहीं किया गया।मुख्यमंत्री आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल पारित न होने के संबंध में आयोजित ‘जन आक्रोश महिला पदयात्रा’ के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन को बाधित करने और सदन में प्रस्ताव को गिराने के विरोध में देशभर में आक्रोश रैलियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और आईएनडीआई गठबंधन के सहयोगियों के विरोध में मातृ शक्ति द्वारा प्रदर्शन किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि जन आक्रोश महिला पदयात्रा में आधी आबादी की बड़ी संख्या में भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के प्रति उनके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक आधी आबादी की जायज मांग का समर्थन करने के लिए तैयार है और महिलाओं के सम्मान व अधिकारों के लिए खड़ा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में अनेक विकास और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। इसी प्रकार प्रदेशों में डबल इंजन सरकारें भी विकास कार्यों को गति दे रही हैं, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दल हर योजना का विरोध करने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन दलों को अपनी महिला विरोधी छवि समाप्त करने का अवसर दिया, लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। आज देशभर में आधी आबादी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री का मानना है कि देश में केवल चार प्रमुख वर्ग हैं—महिलाएं, गरीब, युवा और किसान। इन चारों वर्गों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई गईं, जिससे देश आर्थिक उन्नति के नए सोपानों की ओर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, भारत की विरासत के संरक्षण और समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान की योजनाओं का केंद्र बिंदु आधी आबादी अर्थात नारी शक्ति रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, घरौनी वितरण कार्यक्रम तथा पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों को स्वावलंबी बनाने जैसे प्रयास परिवारों के सशक्तिकरण का आधार बने हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन केवल स्वच्छता अभियान नहीं, बल्कि नारी गरिमा की रक्षा का अभियान भी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए निःशुल्क गैस सिलेंडर ईंधन आपूर्ति का माध्यम होने के साथ-साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा का आधार भी बने हैं। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने का माध्यम बनी है।उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी प्रकार प्रदेश में भी डबल इंजन सरकार इन कार्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सहित अन्य योजनाएं प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही हैं।इस अवसर पर आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल तथा राज्य सभा सदस्य अरुण सिंह ने भी संबोधित किया और महिलाओं के अधिकारों तथा सम्मान के मुद्दे पर अपनी बात रखी।

## ग्रामीण क्षेत्रों की कई अनुसूचित जनजातियों को मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण की प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया

**आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो**

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत भोटिया, जौनसारी, राजी, गोंड तथा इसकी पर्याय धुरिया, ओझा, नायक, पठारी, राजगोंड सहित अन्य कई अनुसूचित जनजातियों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।उप मुख्यमंत्री ने बताया कि गोंड एवं उससे संबंधित पर्याय जातियां—धुरिया, ओझा, नायक, पठारी तथा राजगोंड—उत्तर प्रदेश के महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, कुशीनगर, भदोही तथा संतकबीरनगर जनपदों में निवासरत हैं। इसी प्रकार खरवार एवं खैरवार जातियां देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में, पराहिया जाति सोनभद्र जनपद में, पंखा एवं पनिका जातियां सोनभद्र एवं मिर्जापुर जनपदों में, अगरिया तथा पटारी जातियां सोनभद्र जनपद में तथा भुइंया एवं भुनिया जातियां भी सोनभद्र जनपद में निवास करती हैं।केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि उनके द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान यह मामला संज्ञान में आया कि मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण की पात्रता सूची में उपरोक्त जातियां शामिल नहीं थीं। भ्रमण के दौरान इन जातियों के कई पात्र लोगों द्वारा आवास आवंटन की मांग की गई थी।उन्होंने बताया कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसे संज्ञान में लिया गया तथा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि इन जातियों को भी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण की प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया जाए, ताकि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर इन वर्गों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जा सके।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

## उत्तर प्रदेश में 17 विशेष सचिवों का तबादला, विभिन्न विभागों में नई तैनाती

**आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो**

**लखनऊ।** सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार तात्कालिक प्रभाव से 17 विशेष सचिवों का स्थानांतरण करते हुए उन्हें विभिन्न विभागों में नई तैनाती दी गई है।जारी आदेश के अनुसार विनोद कुमार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सचिवालय प्रशासन विभाग, प्रभात कुमार को चिकित्सा शिक्षा विभाग से ऊर्जा विभाग तथा आनंद प्रकाश सिंह को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में तैनात किया गया है। लाल बहादुर यादव को कृषि विभाग से उपभोक्ता मामले विभाग तथा विनय कुमार सिंह को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से धर्मार्थ कार्य विभाग में भेजा गया है।इसी क्रम में विनीत प्रकाश को नियुक्ति विभाग से सार्वजनिक उद्यम विभाग, जय प्रकाश भारती को सूचना विभाग से खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा सुनील कुमार पाण्डेय को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग से समाज कल्याण विभाग में तैनाती दी गई है। अनिल कुमार को राजस्व विभाग से सहकारिता विभाग तथा मंजूलता सिंह को गृह/गोपन विभाग से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग में भेजा गया है।वेद प्रकाश द्विवेदी को गृह/गोपन विभाग से राजनैतिक पेंशन विभाग, महावीर प्रसाद गौतम को वित्त विभाग से नागरिक सुरक्षा विभाग तथा प्रेम कुमार पाण्डेय को वित्त विभाग से सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात किया गया है। उमा द्विवेदी को संस्कृति विभाग से परिवहन विभाग, आनंद कुमार राय को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से रेशम विकास विभाग तथा संजय शुक्ला को ऊर्जा

## • संक्षेप •

### विश्व पृथ्वी दिवस पर बीबीएयू में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, 22 अप्रैल को राष्ट्रीय संगोष्ठी

लखनऊ। बीबीएयू में 21–22 अप्रैल को ‘विश्व पृथ्वी दिवस’ के अवसर पर भूविज्ञान विभाग और सतत विकास लक्ष्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में द्विदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 21 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिताएं विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के संरक्षण तथा भूविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. नरेंद्र कुमार और सतत विकास लक्ष्य समिति के अध्यक्ष प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा के मार्गदर्शन में आयोजित की गईं।कार्यक्रम समन्वयक एवं भूविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. नरेंद्र कुमार ने कहा कि विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आयोजित इन प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाना और जागरूकता फैलाना है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है और वे अपने दैनिक जीवन में छोटे–छोटे प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित होते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करती है, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें।सतत विकास लक्ष्य समिति के अध्यक्ष प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा ने जानकारी दी कि विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में छह रचनात्मक एवं ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया, जिनमें 200 से अधिक विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी की।

### केजीएमयू में धर्मांतरण रैकेट चलाने वाला गिरफ्तार, शक होने पर छात्रों ने सर्जरी विभाग के पास दबोचा

लखनऊ। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले युवक को छात्रों ने मंगलवार को सर्जरी विभाग के पास से पकड़ लिया। आरोपी हसम अहम खुद को डॉक्टर बताकर छात्र–छात्राओं पर रौब झाड़ता था। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर केके सिंह ने बताया कि हसम अहमद नाम बताने वाला यह शख्स अपने को डॉक्टर बताकर केजीएमयू में घूमता रहता था। स्टुडेंट्स को सीनियर बताकर उन पर रौब झाड़ता था। इसी दौरान वो केजीएमयू की छात्राओं को एम्स दिल्ली ले जाकर कॉन्फ्रेंस का झांसा दिया। हसम अहमद ने पुराने लखनऊ ने कैंप भी लगाया जिसमें केजीएमयू की छात्राएं शामिल हुई थीं। शक होने पर केजीएमयू के छात्रों ने उसे सर्जरी विभाग के पास से पकड़ लिया।

### यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र 30 अप्रैल को, राज्यपाल ने दी मंजूरी, महिला आरक्षण पर होगी चर्चा

**लखनऊ।** यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए यूपी विधानमंडल का सत्र 30 अप्रैल को आहूत किए जाने के लिए मंजूरी दे दी। विशेष सत्र के आहूत किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार ने विवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृति दे दी थी जिसके बाद यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया और राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी। दरअसल, नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पारित न हो पाने पर भाजपा आक्रामक रूप से विपक्ष पर हमलावर हो गई है। रविवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कान्फ्रेंस कर विपक्ष को घेरते हुए कहा था कि संसद में संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान विरोधी दलों का चरित्र भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण जैसा था। यह महिला सम्मान एवं लोकतंत्र दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सरकार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, 30 अप्रैल को आयोजित विधानमंडल के सत्र में सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ विपक्ष पर हमलावर होगी। चर्चा है कि सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है।

## बाल संरक्षण एवं वन स्टॉप सेंटर सेवाओं पर पुलिस कर्मियों का विशेष प्रशिक्षण

**आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो**

**लखनऊ।** पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा बाल संरक्षण एवं महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला रिजर्व पुलिस लाइन स्थित संगोष्ठी सदन में “बाल संरक्षण एवं वन स्टॉप सेंटर सेवाओं” विषय पर आयोजित की गई।यह कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार तथा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) अमित कुमावत के प्रभावी मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यशाला का संचालन सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध/ट्रेनिंग सेल) सौम्या पाण्डेय के पर्यवेक्षण में किया गया।प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अपराध से पीड़ित बालकों एवं महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में पुलिस कर्मियों को जागरूक और दक्ष बनाना था। इसके माध्यम से पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करते हुए पीड़ितों को त्वरित, प्रभावी और संवेदनशील सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया गया।कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थाना क्षेत्रों से नामित 39 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए। प्रशिक्षण सत्र विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किए गए, जिनमें व्यवहारिक एवं तकनीकी दोनों पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

### माध्यमिक शिक्षा मंत्री बोलीं- सपा-कांग्रेस अपने घर की बेटियों को ही बना सकती हैं पीएम-सांसद

**लखनऊ।** माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर सपा, कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने यह विधेयक पास नहीं होने दिया। सपा अपने घर की बेटियों को सांसद और कांग्रेस पीएम और सांसद बना सकती है। लेकिन आम महिला को आगे नहीं बढ़ा सकती है। इनकी असलियत सामने आ गई है। सपा, कांग्रेस ने महिला के हक को मिटाया है। शिक्षकाएं सहयोगी बने, लोगों को बताएं कि इन्होंने क्या किया है। इनकी हकीकत को सामने लाएं। वे गोमती नगर स्थित होटल में आयोजित माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिक्षिकाओं को संबोधित कर रही थीं। मंत्री ने कहा कई दिन से नारी सशक्तिकरण पर चर्चा चल रही है। पीएम ने इसका प्रयास किया है किंतु विपक्ष ने इसे पास नहीं होने दिया।

## शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो**

**लखनऊ।** थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है।पुलिस के अनुसार 15 नवंबर 2025 को पीड़िता द्वारा थाना सरोजनीनगर में तहरीर देकर बताया गया था कि उसकी दोस्ती उवैश अली पुत्र स्वर्गीय उमर अली निवासी आजादनगर थाना सरोजनीनगर, लखनऊ से हुई थी। आरोप है कि अभियुक्त ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा इसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए।पीड़िता के अनुसार बाद में अभियुक्त ने शादी से इंकार कर दिया और शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी दी। इस तहरीर के आधार पर थाना सरोजनीनगर में मुकदमा संख्या 134/26 धारा 69 एवं 351(3) बीएनएस तथा आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर एक धारा का लोप भी किया गया।मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम अभियुक्त की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर 21 अप्रैल 2026 को अभियुक्त उवैश अली, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी आजादनगर थाना सरोजनीनगर को कामर्शियल तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।पूछताछ में सामने आया कि अभियुक्त ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसका वीडियो तैयार किया और बाद में शिकायत करने पर उसे वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी दी।

## फर्जी प्लॉट के दस्तावेज तैयार कर लाखों की धोखाधड़ी करने वाला शातिर गिरफ्तार

**आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो**

**लखनऊ।** राजधानी के थाना पीजीआई पुलिस ने प्लॉट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने और रुपये हड़पने वाले एक शातिर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन, दो पैन कार्ड, तीन डेबिट कार्ड, एक आधार कार्ड तथा एक ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया है।पुलिस के अनुसार 9 जनवरी 2025 को उन्नाव जनपद के बेहटा नथई सिंह, कोरारी कलां निवासी गायत्री देवी द्वारा थाना पीजीआई में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि गौरव अवस्थी और अन्य व्यक्तियों ने मिलकर उन्हें प्लॉट बेचने के नाम पर रुपये हड़प लिए और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी की। इस मामले में थाना पीजीआई पर मुकदमा संख्या 14/2025 धारा 316(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) एवं 351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।मामले की विवेचना के दौरान थाना पीजीआई पुलिस टीम वांछित अभियुक्त की तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में पुलिस टीम तेलीबाग क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त यूनियन बैंक, थाना विभूतिखंड क्षेत्र के पास मौजूद है। सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की और एक व्यक्ति को पकड़ लिया।पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम सर्वेश कुमार पाण्डेय पुत्र ध्यानचन्द्र पाण्डेय, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी रतनखण्ड शारदानगर थाना आशियाना, लखनऊ बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से दो पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और एक पुराना मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के तीन डेबिट कार्ड तथा एक ड्राइविंग लाइसेंस भी उसके कब्जे से बरामद किए गए।पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता है और अवैध तरीके से धन अर्जित कर अपने शौक पूरे करने के उद्देश्य से इस प्रकार के अपराध करता था। पुलिस ने अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त सर्वेश पाण्डेय का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके विरुद्ध थाना आशियाना, थाना सरोजनीनगर तथा जनपद सोनभद्र के थाना करमा में हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य धाराओं में पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं।

## इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच के चलते 22 अप्रैल को कई मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

**आर्यावर्त संवाददाता**

**लखनऊ।** 22 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:00 बजे से मैच समाप्ति तक इकाना स्टेडियम में आयोजित आईपीएल मैच के दृष्टिगत राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। यातायात पुलिस द्वारा जारी सूचना के अनुसार बड़े वाहन, बस, कामर्शियल वाहन तथा सामान्य यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं, ताकि मैच के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित की जा सके।जारी एडवाइजरी के अनुसार कमता शहीद पथ तिराहा अयोध्या रोड से सामान्य यातायात को शहीद पथ के माध्यम से सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड और कानपुर रोड की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन वाहनों को कमता तिराहा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा, समतामूलक चौराहा, करियप्पा चौराहा, तेलीबाग, बाराबिरवा अथवा इंदिरा नहर चौराहा होते हुए किसान पथ से अपने गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। इसी प्रकार शहीद पथ कानपुर रोड तिराहा से भी सामान्य यातायात को सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड और अयोध्या रोड की ओर जाने पर रोक रहेगी और उन्हें वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा।सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड तथा गोसाईगंज क्षेत्र से आने वाले बड़े वाहनों और बसों के लिए भी विशेष डायवर्जन लागू रहेगा। इन्हें अहिमामऊ और शहीद पथ की ओर जाने से प्रतिबंधित किया जाएगा तथा वृंदावन योजना, कबीरपुर किसान पथ और अन्य वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। उतरेठिया अंडरपास चौराहा, लालबत्ती चौराहा और हुसड़िया अंडरपास की ओर से आने वाले वाहनों के लिए भी अलग-अलग डायवर्जन मार्ग निर्धारित किए गए हैं।यातायात पुलिस के अनुसार सुल्तानपुर रोड से आने वाले सामान्य वाहनों को अमूल तिराहा से अहिमामऊ चौराहा की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन वाहनों को अमूल तिराहा से ही डायवर्ट कर लूलू मॉल कटिंग के माध्यम से शहीद पथ पर भेजा जाएगा। वहीं कमता शहीद पथ तिराहा से अहिमामऊ चौराहे पर यू-टर्न लेकर कैण्ट, पुलिस मुख्यालय और गोमतीनगर की ओर जाने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। ऐसे वाहन मेदान्ता अस्पताल के पास से यू-टर्न लेकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।पुलिस ने बताया कि अहिमामऊ चौराहे से प्लासियो मॉल की ओर जाने वाला यातायात पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके स्थान पर वाहनों को एचसीएल तिराहा, संस्कृत तिराहा और ओवरहेड गोल चक्कर होते हुए वैकल्पिक मार्ग से भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त सुल्तानपुर रोड से आने-जाने वाले बड़े वाहनों और बसों को कबीरपुर तिराहा से किसान पथ के माध्यम से संचालित किया जाएगा।यातायात विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे के बीच शहीद पथ पर वाहनों का दबाव अधिक रहने की संभावना है। ऐसे में कानपुर नगर, एक्सप्रेस-वे, बाराबिरवा और अमौसी की ओर जाने वाले वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से शहीद पथ का प्रयोग करने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, जिससे असुविधा से बचा जा सके।

# नए भारत की एमएसएमई क्रांति के केंद्र में है नारी शक्ति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सितंबर 2023 में संसद में समर्थन करते हुए विश्वास व्यक्त किया था कि भारत तभी आगे बढ़ सकता जब देश की नारियां भी इसके साथ ही उन्नति करें। उनका यह विश्वास एमएसएमई क्षेत्र (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) में सरकार के काम में हर रोज दिखाई देता है।

एमएसएमई क्षेत्र को अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो इसके दिल में महिला उद्यमियों का मूक बल बसता है। आखिरकार आज इस मूक बल को वह राष्ट्रीय मान्यता, संस्थागत समर्थन और नीतिगत गति मिल रही है जिसका वह हमेशा से हकदार है। भारत के एमएसएमई इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। 2026 की शुरुआत तक, उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर 3.11 करोड़ से अधिक महिला-नेतृत्व वाले उद्यम पंजीकृत हुए हैं। वास्तव में, उद्यम और उद्यम असिस्ट पंजीकरण के अनुसार, देश के कुल पंजीकृत एमएसएमई में महिला-स्वामित्व वाले उद्यमों की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है और ये रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिला उद्यमियों के लिए सबसे प्रभावशाली सुधारों में से एक उद्यम पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है। पूरी तरह से ऑनलाइन, कागज रहित और स्व-घोषणा पर आधारित इस व्यवस्था ने उस नौकरशाही बाधा को समाप्त कर दिया, जो महिलाओं के लिए एक बड़ी रुकावट बनी हुई थी। जनवरी 2023 में शुरू किए गए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म ने अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत उन महिलाओं तक पहुँच बनाकर इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया, जिनके पास 'पैन नंबर या जीएसटीएन नहीं था। इसने उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋण और सरकारी योजनाओं के लाभों के दायरे में लाने का काम किया। सरकार ने महिलाओं को विकास वाहक के रूप में अपने आर्थिक एजेंडे के केंद्र में रखने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि महिलाओं को सशक्त बनाना केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय रणनीति है। उन्होंने ही कहा था कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो परिवार सशक्त होते हैं और जब परिवार सशक्त होते हैं, तो राष्ट्र निरंतर मज़बूत होता जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीतिक क्षेत्र में इस दर्शन की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता एक व्यापक और बहुआयामी नीतिगत ढांचे के रूप में सामने आई है, जो ऋण, कौशल, बाज़ार तक पहुंच, पहचान और गरिमा जैसे पहलुओं को समाहित करती है।

एमएसएमई मंत्रालय ने अपने हर बड़े कार्यक्रम और योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण को व्यवस्थित रूप से शामिल किया है। ये सभी मिलकर, आपूर्ति पक्ष पर आठ मुख्य श्रेणियों के माध्यम से उद्यमियों को सहायता प्रदान करते हैः तकनीक तक पहुँच, ऋण और वित्त तक पहुँच, डिजिटलीकरण को बढ़ावा, अवसरंचना सहायता, औपचारिकीकरण और समावेशन, बाज़ार तक पहुँच, और उद्योग-स्तरीय कौशल विकास। पिछले पाँच वर्षों में, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 3.2 लाख से ज़्यादा महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को सहायता दी गई है। हाल के आँकड़ों के अनुसार, पीएमईजीपी के कुल लाभार्थियों में से 39त्न महिलाएँ हैं जो इस योजना की रूपरेखा और महिलाओं की कुछ कर दिखाने की ललक, दोनों को दर्शाता है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट महिला ऋणदाताओं को 90 प्रतिशत तक का बढ़ा हुआ गारंटी कवर प्रदान करता है। इससे बैंक बिना कुछ गिरवी रखे महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक खरीद नीति में संशोधन कर यह अनिवार्य किया गया कि केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत हिस्सा महिला-स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से ही खरीदें। इससे महिला उद्यमियों के लिए एक सुनिश्चित और अनुमानित बाज़ार तैयार होता है, जिससे सरकारी खर्च को महिलाओं के व्यवसाय की वृद्धि में बदला जा रहा है। यह देखकर खुशी होती है कि वित्त वर्ष 2025-26 में, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की गई कुल खरीद का 3.5 प्रतिशत हिस्सा महिला एमएसएमई से ही खरीदा गया था। जेडइडी (जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट) प्रमाणन योजना के तहत, महिला-स्वामित्व वाले एमएसएमई को प्रमाणन शुल्क पर सौ प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। ये विस्तृत विवरण काफी महत्वपूर्ण हैं और ये मंत्रालय के प्रयासों को दर्शाते हैं। मंत्रालय ने इस बारे में गहराई से विचार किया है कि महिलाओं को कहाँ कहाँ बाधाओं का सामना करना पड़ता है और ठीक उन्हीं बाधाओं को दूर करने के लक्ष्य के साथ सहायता दी गई।

# बिहार में विकास सम्बन्धी चुनौतियों को अवसरों में बदलना होगा नए सम्राट को!

**कमलेश पांडे**

> बिहार में 26 साल पहले हुए राज्य विभाजन के बाद औद्योगिक आधार छोटा हुआ है, क्योंकि अधिकांश बड़े उद्योग-धंधे झारखंड के हिस्से में चले गए।

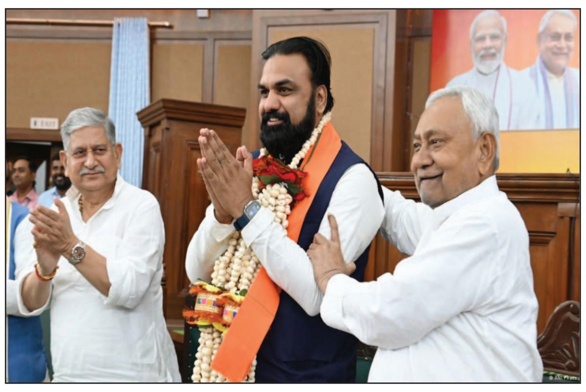

बिहार के नए सम्राट को फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज मिला है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, या पूर्व मुख्यमंत्री दम्पत्ति लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, कभी भी चैन पूर्वक राज नहीं कर सके। लिहाजा, मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी उन जातीय और साम्प्रदायिक चुनौतियों से जूझना होगा, जो बिहार के विकास में शुरू से ही बाधक समझी गई हैं। लेकिन जिस प्रकार से आधुनिक बिहार के निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा को कांग्रेस के सहयोग से लंबे समय तक राज करते हुए जनसेवा का मौका मिला, वैसी ही मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भाजपा के सहयोग से जनसेवा का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा भी है कि पार्टी ने उन्हें पद नहीं, जनसेवा का अवसर दिया है, इसलिए विकास, सुशासन और समृद्धि उनके शासन का मूलमंत्र होगा।

बिहार के आर्थिक विश्लेषक बताते हैं कि बिहार के विकास में श्रीकृष्ण सिन्हा के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ी रेखा खींचने की कोशिश की, प्रगति नजर भी आई, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और हाल के वर्षों में उत्तरप्रदेश के विकास को देखा जाए तो अब भी बिहार के विकास में कई बड़ी बड़ी चुनौतियाँ बाकी हैं, जो आंकड़ों और राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखने पर साफ दिखती हैं। इसलिए भाजपा की सरकार के सुलझे हुए और समावेशी प्रवृति वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी बिहार के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित चुनौतियों से जूझना होगा। लेकिन अपने मृदु स्वभाव से वे एक एक करके इनसे पार पा जाएंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है।

आंकड़े बताते हैं कि बिहार, भारत के सबसे कम आय वाले राज्यों में शुमार है, जहां गरीबी दर अभी भी काफ़ी ऊँची है और रोज़गार की गुणवत्ता कमज़ोर है। समझा जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश कम होने के कारण यहां की “मानव पूंजी” कमज़ोर है- साक्षरता और स्किल लेवल अभी भी देश के स्तर से काफी नीचे हैं, जिससे युवाओं को अच्छे रोज़गार के अवसर मिलने में दिक्कत होती है। ऐसे में यदि अपराध, जातीय सोच और सांप्रदायिक मिजाज को हतोत्साहित करके इन लक्ष्यों को पाया जा सकता है। इसके लिए अप्रवासी बिहारियों और बिहार मूल के एनआरआई को आकर्षित करने वाली योजनाओं को बनाना होगा और उनपर दृढ़तापूर्वक अमल करना होगा।भारत खबर अपडेट

यद्यपि हार की आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन उत्पादकता और आय दोनों ही अपेक्षाकृत कम हैं। ऐसा इसलिए कि उत्तर बिहार 4 महीना बाढ़ से आक्रांत रहता है और तभी दक्षिण बिहार सूखा से जूझ रहा होता है। खेती और बागवानी यहां पर होती तो है, लेकिन भंडारण सुविधाएँ, बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और बारहमासी सिंचाई की सीमित पहुँच जैसे कारकों के कारण कृषि अभी भी बहुत जोखिम भरी और कम लाभ वाली काम साबित होती है। लिहाजा किसानों और मजदूरों के बच्चे परदेश कमाने चले जाते हैं और अपनी उद्यमिता से सबको सुख पहुंचाते हैं।

बिहार में 26 साल पहले हुए राज्य विभाजन के बाद औद्योगिक आधार छोटा हुआ है, क्योंकि अधिकांश बड़े उद्योग-धंधे झारखंड के हिस्से में चले गए। ततपश्चात छोटे और कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग तकनीकी पिछड़ेपन और वित्तीय अभाव के कारण इनका समग्र विस्तार नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति को बदलना होगा। इस कारण और निजी निवेश की दृष्टि से बिहार अभी भी “निवेश अनुकूल” राज्यों की पहली पंक्ति में नहीं है, बल्कि तेज़ी के साथ उद्योग बढ़ाने की चुनौती बरकरार है। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को चाहिए कि वह महाराष्ट्र और गुजरात की तर्ज पर बिहार-उत्तरप्रदेश में औद्योगिक विकास की गति तेज करे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में औद्योगिक रफ्तार तेज होने से लुक ईस्ट की विदेश नीति को मजबूत आधार मिलेगा।

बिहार में सड़क नेटवर्क, बिजली, जल सुविधा, नालियाँ, जनस्वास्थ्य और शहरी बुनियादी ढांचा अभी भी प्रमुख रूप से कमज़ोर जगह बनी हुई हैं। चाहे स्थापित शहर हों या कस्बाई शहर, यहां शहरीकरण बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिससे औद्योगिक सेवा अर्थव्यवस्था को उतना बल नहीं मिल पा रहा जितना दूसरे विकसित राज्यों में मिला है। इसलिए नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि रोजगार के सृजन में इस क्षेत्र का बड़ा इगड6 होता है।

बिहार के शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएँ बेहद कमज़ोर हैं- खासकर डॉक्टर आबादी अनुपात कम, स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है और कुपोषण जैसी समस्याएँ अभी भी गंभीरबनी हुई हैं। इसी तरह पीडीएस (PDS), राशन, योजनाओं के वितरण में धांधली, रिसाव और कार्यान्वयन की कमज़ोरी विकास के लाभों को गरीबों तक पहुँचने से रोकते हैं। इस स्थिति में अमूलचूल बदलाव लाना होगा, ताकि स्थिति बदले।

बिहारी में जब भी नेतृत्व परिवर्तन होता है तो शासन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में बदलाव की उम्मीदें बंधती हैं, लेकिन बाद में सबकुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। अब इस स्थिति को बदलना होगा। क्योंकि कई रिपोर्टों में बिहार को भ्रष्टाचार, निष्पक्ष नियोजन और प्रशासनिक दक्षता की दिक्कत से जूझता हुआ देखा गया है, जिससे बजट का अच्छे तरीके से उपयोग होना मुश्किल होता है। वहीं, कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी निवेशक और नागरिक दोनों के लिए चिंता का मुद्दा है। इसलिए नए मुख्यमंत्री को इसे समझना होगा और विशेष टास्क फोर्स का गठन कर इस स्थिति को बदलना होगा। इसी में बिहार का हित निहित है।

## टिप्पणी

# सामाजिक दायित्व की संकुचित समझ की मिसाल

तेलंगाना विधानसभा ने 'कर्मचारी उत्तरदायित्व एवं माता-पिता की सहायता निगरानी अधिनियम बिल-2026Ó को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रावधान है कि राज्य में सरकारी या निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी अथवा जन प्रतिनिधि अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करेंगे, उनकी तनख्वाह में से 15 प्रतिशत या 10,000 रुपये (इनमें जो कम होगा) काट कर उसे उनके माता-पिता को दे दिया जाएगा। राज्य सरकार का दावा है कि इस तरह वह 2007 में माता- पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण के लिए बने केंद्रीय कानून से आगे गई है। इस तरह उसने अपना सामाजिक दायित्व निभाया है। मगर यह सामाजिक दायित्व निभाने से कहीं ज्यादा निभाते हुए दिखने का प्रयास भर है।

एक समस्या यह है कि राज्य सरकार की सारी चिंता संगठित क्षेत्र में मौजूद कर्मचारियों के माता-पिता तक सीमित रह गई है। राज्य की कुल श्रम शक्ति में बमुश्किल 20 फीसदी कर्मचारी औपचारिक क्षेत्र में हैं। तो अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मियों के माता-पिता की देखभाल कैसे होगी? वैसे भी पारिवारिक या सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए किसी बाध्य करना समस्याग्रस्त सोच है। जो कठिनाइयां सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव से खड़ी हुई हैं, उनका अतीत से प्रेरित दृष्टिकोण से समाधान ढूंढना निरर्थक प्रयास है। तेलंगाना सरकार को ये कदम उठाने से पहले समीक्षा करनी चाहिए थी कि 2007 के केंद्रीय कानून से क्या हासिल हुआ? तब उसके सामने स्पष्ट होता कि बुजुर्गों की ऐसी देखभाल के लिए अलग उपायों की जरूरत है, जिससे वे आत्म-सम्मान के साथ जी सकें।

राज्य सरकार तेलंगाना में आधुनिक सुविधाओं एवं चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था के साथ सरकारी क्षेत्र में वृद्धावस्था आश्रमों का जाल बिछाने का फैसला करती, तो वह सारे देश के लिए एक मिसाल पेश कर सकती थी। इसके लिए प्रगतिशील कराधान से धन जुटाने की पहल सही सोच होती। लेकिन उसने जबरन तनख्वाह काट कर नकदी माता- पिता को देने का जो नजरिया अपनाया है, उससे वृद्धों को उपेक्षित जिंदगी जीने की समस्या से नहीं बचाया जा सकेगा। इस सतही प्रयास का अधिक से अधिक सीमित लाभ ही होगा। स्पष्टतः यह सामाजिक दायित्व की संकुचित समझ की मिसाल है।

## ब्लॉग

# वैश्विक तनाव के बीच भारत की सधी हुई चाल, ऑस्ट्रिया के साथ सहयोग बढ़ाकर मोदी ने किया कमाल

**सुश्री शोभा करंदलाजे**

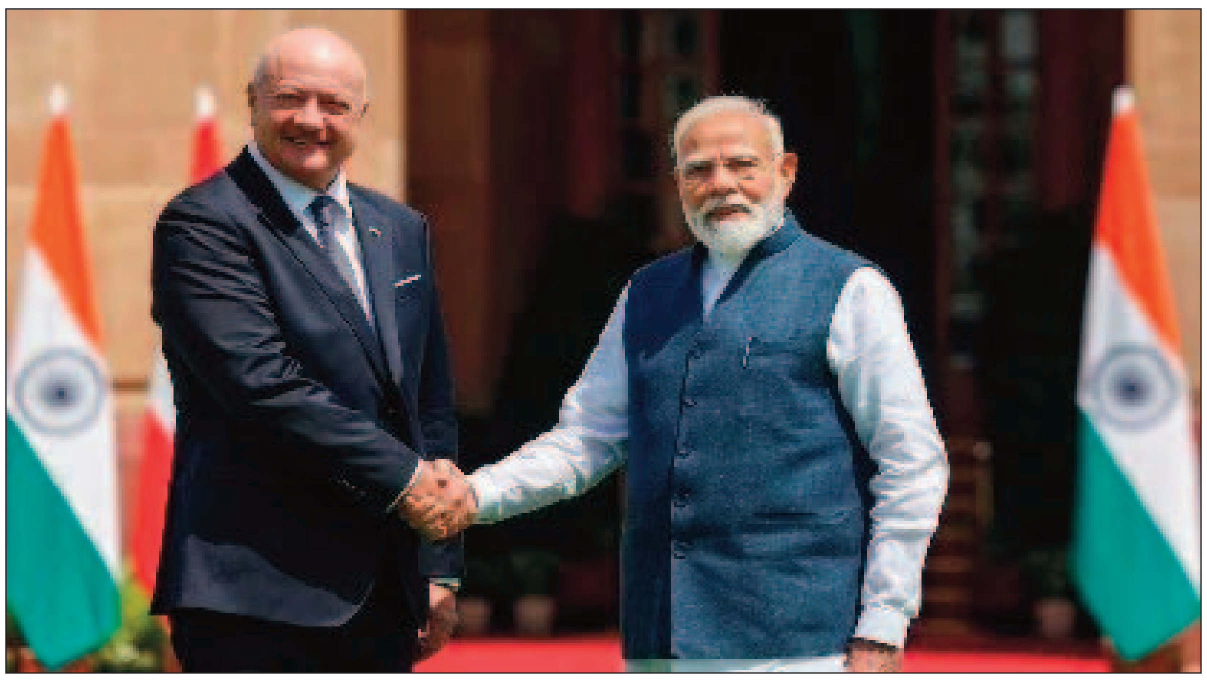

एक राज्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लेते समय, मैंने उस खचाखच भरे कमरे में चारों ओर नजरें घुमायीं और गिनती की। वहां मौजूद महिलाओं की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। इस दृश्य ने केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में ही नहीं, बल्कि इस बात के स्पष्ट संकेत के रूप में भी एक छाप छोड़ी कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को अभी भी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है।

मैं कर्नाटक के तटीय इलाके के पुत्तूर के पास स्थित एक छोटे से गांव से आती हूं। पारंपरिक रूप से यह एक समृद्ध इलाका है और यहां की महिलाओं ने हमेशा अपनी दृढ़ता एवं शक्ति का परिचय दिया है। मुझे पता है कि उस शक्ति को सार्वजनिक जीवन में लगाने का क्या मतलब होता है। खासकर, उस स्थिति में जब एक ऐसी राह पर चलना हो जिस पर पहले चंद लोग ही चले हों और हर महिला को वैसे ही जोश के साथ वैसा ही मौका नहीं मिला हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही पारित हो चुका है। संसद में सितंबर 2023 में इस पर चर्चा हुई थी और संविधान में संशोधन किया गया था। लेकिन अब उस वादे को निभाने का सबसे मुश्किल काम सामने है।

भारत में कुल 670 मिलियन महिलाएं हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों में महज 15 प्रतिशत महिलाएं ही संसद में पहुंच पायीं हैं। जो लोकतंत्र अपने आधे नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से लगातार बाहर रखे, उसे सच्चा लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोकतंत्र को विकास की प्रक्रिया में ही माना जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन कागज पर लिखे किसी कानून का तभी कोई महत्व होता है, जब उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जनगणना कराना बेहद जरूरी है। इसके बाद परिसीमन होना चाहिए और संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

जब कानून बनाने वाली प्रक्रियाओं में महिलाओं को शामिल किया जाता है, तो कानून बनाने का केन्द्रबिंदु ही बदल जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में, जहां दशकों पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था, प्राथमिकताओं में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है। पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के पोषण के लिए अधिक बजट आवंटित किए गए। भ्रष्टाचार के प्रति कम सहनशीलता और समुदायों के प्रति अधिक जवाबदेही देखी गई। यह महज एक संयोग नहीं है। यह प्रतिनिधित्व का जीता-जागता उदाहरण है। मैंने अक्सर यह तर्क सुना है कि महिलाओं को अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस भावना का सम्मान करती हूं। लेकिन इस आधार को खारिज करती हूं। योग्यता शून्य में नहीं पनपती। यह वहीं पनपती है, जहां अवसर मौजूद होते हैं। पीढ़ियों से, संरचनात्मक बाधाओं - सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक - ने प्रतिभाशाली महिलाओं को राजनीति से बाहर रखा है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में हमेशा उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी गई है जिनके पास सुस्थापित नेटवर्क एवं संपर्क तथा विरासत में मिली राजनीतिक साख रही है और जो घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। दूसरी ओर, महिलाओं को इनमें से कोई भी सुविधा हासिल नहीं है।

जब बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायतों में दाखिल हुईं, तो शुरू में उन्हें नजरअंदाज किया गया। आखिरकार, विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया कि उनके अपने समुदायों ने उन्हें उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक प्रभावी, अधिक सुलभ और अधिक ईमानदार माना। जब महिलाओं को उचित अवसर दिया जाता है, तो वे केवल भाग ही नहीं लेती बल्कि नेतृत्व भी करती हैं।

सरकार में रहते हुए अपने व्यापक अनुभवों से मैंने यह जाना है कि निर्णय लेने वाले स्थानों पर आपकी मौजूदगी ही इस बात को निर्धारित करती है कि किस विषय पर चर्चा होगी। महिला जनप्रतिनिधि मातृ स्वास्थ्य निधि में कटौती की आशंका होने पर इसके लिए आवाज उठाती हैं। वे उन नीतियों के लैंगिक प्रभाव को उजागर करती हैं, जिनका व्यवहार में सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ सकता है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की उन चिंताओं को सामने लाती हैं, जिनसे उनके पुरुष सहकर्मियों का सामना नहीं होता।

संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का मतलब यह है कि पहली बार ये आवाजें अपवाद नहीं रहेंगी। ये आवाजें ढांचागत व्यवस्था का हिस्सा होंगी। स्थायी होंगी। इन्हें नजरअंदाज करना असंभव होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह मानना रहा है कि भारत अपनी महिलाओं की पूर्ण और बराबरी की भागीदारी के बिना अपनी पूरी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर सकता। यह महज एक बयानबाजी भर नहीं, बल्कि एक ऐसा दृढ़ विश्वास है जिसने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर 'जन धन, 'उज्ज्वला और 'प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी वाली नीतियों को दिशा दी है। उन्होंने नारी शक्ति को केवल एक नारा नहीं, बल्कि विकसित भारत का आधार बताया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सोच की पूर्ण अभिव्यक्ति है। यह सोच महिला सशक्तिकरण को कल्याणकारी योजनाओं से आगे बढ़ाकर शासन की संरचना में समाहित करती है।

यह क्षण हम सभी का है। यह मौका किसी एक दल का नहीं, बल्कि एक संस्था के रूप में संसद का है। सरकार के हर स्तर पर इस राष्ट्र की सेवा करने वाली एक महिला के रूप में, मैं सभी से अपील करती हूं और मेरा मानना है कि हम सभी भारत के लोकतंत्र को मजबूत और अधिक पूर्ण देखना चाहते हैं। भारत की महिलाओं के प्रति हमारा अब यह कर्तव्य है कि हम जनगणना कराने, परिसीमन के कार्य को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने में तत्परता बरतें कि इस प्रक्रिया में एक भी दिन अनावश्यक रूप से बर्बाद न हो।

मैं कार्यान्वयन, आरक्षित सीटों के चक्रण (रोटेशन), परोक्ष (प्रॉक्सी) उम्मीदवारों और सनसेट क्लॉज से जुड़ी चिंताओं से अवगत हूं। ये जायज बहसें हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन पर तत्काल ध्यान दिया जाए। सिद्धांत सही है। जरूरत तत्परता की है। हमें पूर्णता को परिवर्तनकारी कदमों के आड़े नहीं आने देना चाहिए। सितंबर 2023 में इतिहास रचा गया था। लेकिन इतिहास सार्थक तभी होता है जब उसके बाद की घटनायें भी मायने रखें। एक न्यायप्रिय देश अपने द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करके चुपचाप एक चिरस्थायी बदलाव को संभव बनाता है। अपने देश की सेवा करने की आकांक्षा रखने वाली हर युवती, मंच से हमेशा वंचित रहने वाली हर नेता और अभिव्यक्त होने से वाचित हर आवाज के हित में, अब काम करने का समय है।

इस कानून को लागू कीजिए। दायरे का विस्तार कीजिए। सारा देश देख रहा है।

**लेखिका केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम और रोजगार राज्यमंत्री हैं**

# 'गिड़गिड़ाते रहे बच्चे, पैरों में गिर गए थे...', फिर भी न पसीजे 'कातिल', बच्चों के सामने मां-बाप का कत्ल

आर्यावर्त संवाददाता

**मुरादाबाद।** मुरादाबाद शहर के चक्कर की मिलक में रामगंगा किनारे बने मकान में सोमवार की रात आठ बजे हुई वारदात ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। मात्र 16 हजार रुपये को लेकर पनपे विवाद में पड़ोसी के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजा और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। बेटी अफ्शा और बेटा आतिफ गिड़गिड़ाते रहे। हमलावरों के पैरों में गिर गए, लेकिन फिर भी हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। राजा और फराह की मौत होने तक चाकू से वार करते रहे। आठ साल की अफ्शा ने पुलिस को बताया कि उन लोगों को भी पीटा।

अफ्शा ने बताया कि छोटे भाई अब्बास की कई दिन से तबीयत खराब चल रही थी। सुबह पापा काम पर चले गए थे। शाम को घर आए थे। मां दिन भर अब्बास के पास ही चारपाई पर बैठी रही थी। मम्मी-पापा अब्बास की दवाई लेकर आए थे।

घर में आकर पापा एक चारपाई पर बैठे थे। दूसरी चारपाई पर मां और अब्बास थे। मैं और दूसरा भाई मकान के बाहर मौजूद थे। अभी घर में खाना भी नहीं बना था। इसी दौरान वे लोग हमारे घर में घुस आए। उन्होंने पापा से मारपीट शुरू कर दी थी।

शोर शराबा होने पर अब्बास रोने लगा तो मां ने उसे गोद में ले लिया और पिता को बचाने लगी थी। हम दोनों भाई बहन भी कमरे में आ गए थे। उन्होंने ने पिता पर चाकू से हमला कर दिया। मां बचाने आई तो उन पर भी वार किए थे।

अफ्शा और उसका भाई आरोपियों ने सामने गिड़ड़िाए की हमारे मां-बाप को छोड़ दो लेकिन आरोपियों को कोई रहम नहीं आया। भाई बहन ने चीख पुकार मचाई और भागकर पड़ोस में रह रहे चाचा सुहैल और दादा नसीम को बुलाने गए। इसके बाद आस पड़ोस के लोग भी आ गए लेकिन तब तक हत्यारोपी मौके से भाग गए थे।

### दरवाजा बंद कर भाग गए आरोपी के परिजन

पति पत्नी की हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार के लोगों से पूछताछ की तब पता चला कि हत्यारोपी भी इसी मोहल्ले में रहते हैं। पुलिस टीम ने फहीम के घर में दबिश दी तो पता चला कि आरोपी दरवाजा बंद कर भाग गए हैं। पुलिस ने धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया लेकिन घर में दस साल की एक बच्ची ही मिली।

### राजा की मां बोली, हत्यारों को मिले फांसी की सजा

राजा के पिता नसीम, भाई सुहैल और मां रानी पास में ही पैतृक मकान में रहते हैं। एक साल पहले तक राजा भी इसी मकान में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था लेकिन उसने मेहनत मजदूरी करने के बाद किसी तरह दो लाख रुपये जुटाकर मकान खरीद लिया था। राजा के पिता नसीम ट्रक ड्राइवर हैं। राजा की मां रानी ने रोते हुए कहा कि हत्यारोपी उसके बेटे और बहू की हत्या करने के बाद भाग गए। तीन मासूम बच्चे अनाथ हो गए। रानी ने कहा, हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए।

### बैकअप देने के लिए गली में था फहीम

इस दोहरे हत्याकांड को अचानक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। फरजंद अपने चचेरे भाई और दोस्त के साथ राजा के घर में पहुंचा था तो फहीम कुछ ही दूरी पर गली में बैकअप देने के लिए खड़ा था। अगर राजा और उसकी पत्नी की चीख-पुकार सुनकर उसके परिजन आए तो राजा के घर से फरजंद और उसके साथियों को कैसे बाहर निकाला जा सकता था। यह जानकारी पुलिस की हिरासत में आए फहीम ने पूछताछ में कबूली है।

### राजा और फराह ने किया था प्रेम विवाह

करीब दस साल पहले राजा और फराह ने प्रेम विवाह किया था। फराह का परिवार भी चक्कर की मिलक में ही रहता है। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं। दोनों के परिवार पहले से रिश्तेदार हैं। फराह और राजा ने शादी करने क प्रस्ताव परिवार के लोगों के सामने रखा तो वह तैयार हो गए थे। राजा और फराह अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी के साथ रह रहे थे। लेकिन सोमवार की रात इस दोनों की जिंदगी का दुखद अंत हो गया।

### मुरादाबाद में बच्चों के सामने मां बाप को चाकुओं से गोदकर मार डाला

मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना इलाके के चक्कर की मिलक में सोमवार की रात आठ बजे घर के भीतर बच्चों के सामने राजा (30) और उसकी पत्नी फराह (26 ) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग आए तो हत्यारोपी मौके से भाग गए। पुलिस का कहना है अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मकान को लेकर कोई विवाद है। यह मकान एक साल पहले खरीदा गया था। मगर अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

एसएसपी सतपाल अंतिल के मुताबिक सिविल लाइंस के चक्कर की मिलक निवासी राजा (30) ने करीब एक साल पहले पड़ोसी फहीम से रामगंगा किनारे बना एक कमरे का मकान दो लाख 24 हजार रुपये में खरीदा था। पॉलिश का काम करने वाले राजा ने दो लाख रुपये देकर मकान पर कब्जा ले लिया था।

राजा इस मकान में अपनी पत्नी फराह (30), बेटी अफ्शा (8), बेटे आतिफ (5) और डेढ़ साल के दूसरे बेटे अब्बास के साथ रह रहा था। फहीम ने मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई गई थी। अब फहीम 24 हजार के बजाए 40 हजार रुपये लेकर मकान की रजिस्ट्री कराने की बात कर रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम भी राजा और फहीम के बीच विवाद हुआ था। राजा ने फहीम की पिटाई की तो उसके हाथ में चोट आ गई थी। सोमवार की रात करीब आठ बजे राजा और उसकी पत्नी फराह कमरे में मौजूद थे।

डेढ़ साल के बेटे अब्बास की तबीयत खराब थी और वह चारपाई पर लेटा हुआ था। जबकि बेटी अफ्शा और आतिफ मकान के सामने ही खेल रहे थे। इसी दौरान फहीम का बेटा फरजंद, अपने चचेरे आई और एक अन्य युवक के साथ राजा के घर में आ गया। आरोपियों ने राजा के साथ मारपीट शुरू कर दी। पत्नी बचाने आई तो उसके साथ मारपीट की। शोर शराबा सुनकर बेटी और बेटा भी कमरे में आ गए। इसके बाद आरोपियों ने बच्चों के सामने ही दोनों पर चाकुओं से हमला कर दिया। चाकू के दस से ज्यादा वार किए गए हैं। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस अधिकारियों के साथ डीआईजी मुनिराज ने भी घटना स्थल पर पहुंचे।

## पेंशनर्स के टर्म्स रिफरेन्स को जोड़े जाने तक संघर्ष का एलान

**जौनपुर।** सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की जनपद इकाई ने कलेक्ट्रेट परिसर मे जनपद अध्यक्ष बी सिंह की अध्यक्षता में एकत्र होकर बिरोध प्रदर्शन किया। धरना-प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र के आठवे वेतन आयोग के संकल्प पत्र मे पेंशनर्स के टर्म्स रिफरेन्स को सम्मिलित किए जाने सहित दस सूत्रीय मांग को लेकर आज देश भर मे आल इण्डिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फेडरेशन के देश व्यापी बिरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को प्रदेश के सभी जनपदो मे संगठन कर रहा है। केंद्र सरकार वित्त बिधेयक 2025 के माध्यम से पेंशनर्स मे सेवानिवृत्त की तिथि के आधार पर विभेद कर रहा है,जिससे वेतन आयोग के परिधि से जनवरी 2026 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स बाहर हो गए है,।जिसके कारण प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश के पेंशनर्स आक्रोशित और आन्दोलित है।

## पूर्व मंत्री अरूण कुमार की राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई

आर्यावर्त संवाददाता

**जौनपुर।** उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह मुन्ना के निधन हो जाने पर उनके पैतृक आवास रामनगर कोट पर पहुंच कर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष डा प्रमोद कुमार सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ खान एवं पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प एवं पार्टी का तिरंगा अर्पित कर नमन किया। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष डा प्रमोद कुमार सिंह जी ने कहा कि छात्र राजनीति एवं यूथ कांग्रेस से अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत करने वाले स्व.अरुण कुमार सिंह मुन्ना का सम्पूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी की मजबूती और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहा, वे जौनपुर जिले की रारी विधानसभा से विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री के पद को सुशोभित किया है। कांग्रेस संगठन में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बाद सन 2003 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान किया था। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि आज हमने एक स्पष्टवादी व, बेबाक नेता खो दिया, स्व. अरुण कुमार सिंह मुन्ना का सम्पूर्ण जीवन गांधी के सिद्धांतों पर आधारित था। वे सत्य को भी अपना प्रमुख सिद्धांत मानते थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सत्यवीर सिंह ने कहा कि अरुण कुमार सिंह के रूप में कांग्रेस का एक स्तंभ इस दुनिया से चला गया, उनके स्थान की पूर्ति संभव नही है। सत्यवीर सिंह ने कहा कि स्व.अरुण कुमार सिंह का व्यक्तित्व बहुआयामी था, जरुरतमंदों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तैयार मिलते थे, गांधी नेहरू परिवार की उनकी निकटता छात्र जीवन से ही थी। कांग्रेस पार्टी सेवादल के मुख्य जिला संगठक आरिफ सलमानी ने अपने नेता को सलामी देकर अंतिम विदाई दी।

## बूढ़ी मां को लोहे की रॉड से इस कदर पीटा, अस्पताल में करनी पड़ी भर्ती, वजह सुन रह जाएंगे हैरान

आर्यावर्त संवाददाता

**एटा।** एटा के अलीगंज कस्बे के मोहल्ला काजी में गुस्से में आकर एक युवक ने अपनी वृद्ध मां पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। परिवार के अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप पर वृद्धा की जान बचाई जा सकी। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस घायल वृद्धा के बड़े बेटे की तलाश कर रही है।

मोहल्ला काजी में बनवारी लाल का परिवार रहता है उनके दो बेटे-बहू साथ में रहते हैं। बनवारी लाल की वृद्ध पत्नी निर्मला देवी रविवार की रात को बिजली न होने पर गर्मी से परेशान होकर घर के बाहर सो रहीं थीं। इसकी जानकारी होने पर बड़े बेटे रमेश ने आपत्ति जताई, इस पर मां-बेटे में विवाद हो गया। गुस्से में आवेश खो बैठे रमेश ने लोहे की रॉड से अपनी मां पर हमला कर दिया। पैरों पर कई वार किए जाने से वह बुरी तरह घायल हो गईं।

चीखपुकार सुन पड़ोसी और उनका छोटा बेटा ब्रजेश, उसकी पत्नी ने हस्तक्षेप कर वृद्धा को बचाया। खून बहने पर वृद्धा को अस्पताल ले जाया गया। सोमवार की सुबह जानकारी होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पड़ताल शुरू कर वृद्धा के हमलावर बेटे रमेश की तलाश शुरु कर दी है। थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने कहा मामले की जानकारी होने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है तहरीर न मिलने पर भी वृद्ध मां के हमलावर पर कार्रवाई की जाएगी।

# पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर गरजेंगे लड़ाकू विमान

आर्यावर्त संवाददाता

**सुलतानपुर।** बुधवार को जनपद के अरवल कीरी करवत स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर एक बार फिर वायुसेना के लड़ाकू विमानों का रोमांचक अभ्यास होने जा रहा है। 22 व 23 अप्रैल को मध्य वायु कमान के निर्देशन में यह विशेष युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। करीब चार किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी को पूरी तरह वायुसेना की निगरानी में रखा गया है। सोमवार देर सायं वायुसेना के एयर कॉरिडोर अधिकारी योगेश इस्सर विशेष हेलीकॉप्टर से पहुंचकर तैयारियों का गहन निरीक्षण किया।

### पहले भी हो चुका है अभ्यास

इससे पूर्व वर्ष 2019 और 2023 में भी इसी हवाई पट्टी पर वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान/सुखोई, मिराज, जगुआर, राफेल सहित अन्य विमानों ने सफलतापूर्वक युद्धाभ्यास किया था। एक बार फिर इन जांबाज विमानों की गूंज से क्षेत्र का आसमान दहलेगा।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम यूपीडा के कार्यकारी अधिकारी विनीत पांडे ने बताया कि हवाई पट्टी पर शेष सभी कार्य मंगलवार सायं तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। वहीं मध्य वायु कमान के जनसंपर्क अधिकारी अश्विनी दुबे के अनुसार, अभ्यास के दौरान सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं।

### यातायात मार्ग में बदलाव

अभ्यास के मद्देनजर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है। लखनऊ से गाजीपुर जाने वाले वाहन गुप्तारगंज (किमी 124) से उतरकर अयोध्या-प्रयागराज मार्ग होते हुए कूरेभार, फिर हलियापुर-बेलवाई मार्ग से फुलौना के पास (किमी 129.8) दोबारा एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे। वहीं गाजीपुर से लखनऊ जाने वाले वाहन गौरा के पास से परिवर्तित मार्ग से होकर फुलौना, बेलवाई, हलियापुर होते हुए गुप्तारगंज के पास सर्विस लेन से एक्सप्रेसवे पर पहुंचेंगे।

### प्रशासन की अपील

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित डायवर्जन का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, ताकि वायुसेना का यह महत्वपूर्ण अभ्यास सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इस अभ्यास को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और लोग एक बार फिर आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना देखने को उत्सुक हैं।

## रास्ते के विवाद ने लिया खूनी रूप, फायरिंग से फैली दहशत, भीषण पथराव से मची भगदड़, मथुरा बवाल का लाइव वीडियो

आर्यावर्त संवाददाता

**मथुरा।** मथुरा के थाना जैत क्षेत्र के गांव राजपुर बांगर में सोमवार रात रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षो के लोग आमने-सामने आ गए। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव हुआ, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे आगरा रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब 10:30 बजे गांव निवासी मनीष और राहुल अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से दीपक अपनी कार लेकर आ गया। रास्ता क्रॉस करने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे लेकर निकल आए और एक-दूसरे पर हमला बोल दिया। संघर्ष के दौरान दोनों ओर से जमकर ईंट-पत्थर चले। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मौके पर कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिससे गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही थाना जैत पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। एक पक्ष से राहुल के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसे वृंदावन के सौ-शैय्या अस्पताल से आगरा रेफर किया गया है। मनीष को भी मामूली चोटें आई हैं।

वही दूसरे पक्ष से राजेश सैनी घायल हुए हैं, जिनका पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया है। पुलिस ने फायरिंग फायरिंग की पुष्टि होने से इंकार कर दिया है। वहीं एक वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी फायरिंग होने की बात कहता दिखाई दे रहा है और पीछे से धमाके की आवाज भी आ रही है। घटना के संबंध में जैत थाना प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि फायरिंग की सूचना भ्रामक है। पास ही एक शादी समारोह में पटाखे चल रहे थे, जिसे लोगों ने गोली चलने की आवाज़ समझ लिया। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

# जिंदा समाधि की जिद पर अड़े महंत, मठ में हाई वोल्टेज ड्रामा, एसडीएम-सीओ मनाने में जुटे

आर्यावर्त संवाददाता

**बाराबंकी।** यूपी के बाराबंकी में असंद्रा थाना क्षेत्र के भवनियापुर स्थित श्रीराम जानकी मठ मंगलवार को संवेदनशील केंद्र बन गया। यहां महंत मुकुंदपुरी की जिंदा समाधि की घोषणा ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। मठ परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही महंत को मनाने में जुटे हैं। हर पल स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

मठ की जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया है। महंत मुकुंदपुरी का आरोप है कि एक व्यक्ति ने फर्जी और अपंजीकृत वसीयत के आधार पर मठ की करोड़ों की संपत्ति अपने नाम दर्ज करा ली थी। इस पर तहसील प्रशासन ने 24 अगस्त 2023 को कार्रवाई करते हुए वसीयत को निरस्त कर मूल खातेदार के नाम संपत्ति दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही 45 दिनों में समाधान का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन फाइलों में उलझा मामला जमीन पर नहीं उतर सका।

### आश्वासनों से निराश महंत ने अल्टीमेटम दे दिया

इसी देरी ने अब हालात को विस्फोटक बना दिया है। प्रशासनिक आश्वासनों से निराश महंत ने अल्टीमेटम दे दिया था। 20 अप्रैल तक कार्रवाई नहीं तो 21 अप्रैल को जिंदा समाधि। अब तय तारीख पर वह अपने फैसले पर अड़े हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। खबर फैली तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जुट गए।

### मौके पर मौजूद प्रशासनिक टीम

एसडीएम, सीओ और थाना पुलिस लगातार संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, महंत को समझाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है।

पुलिस के अनुसार, यह पहला मौका नहीं है जब महंत ने ऐसा कदम उठाने की चेतावनी दी हो। वर्ष 2023 में भी इसी तरह की घोषणा की गई थी, जिसे प्रशासनिक हस्तक्षेप से टाल दिया गया था। लेकिन इस बार स्थिति ज्यादा गंभीर और जिद अधिक कड़ी नजर आ रही है।

## नवनिर्मित तहसील का नया भवन बनकर तैयार, शिफ्टिंग का इंतजार

आर्यावर्त संवाददाता

**बल्दीराय/सुलतानपुर।** नवनिर्मित तहसील बल्दीराय का नया भवन पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक तहसील कार्यालय को वहां स्थानांतरित नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर कब तहसील कार्यालय नए भवन में शिफ्ट होगा।

वर्तमान में तहसील कार्यालय डाकबंगले के अस्थायी भवन में संचालित हो रहा है, जहां सीमित संसाधनों व अव्यवस्था के चलते आम जनता और कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नया भवन तैयार होने के बावजूद शिफ्टिंग में हो रही देरी से आम जन में तरह तरह के सवाल उठ रहे है वही बार ऐसोशिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह का कहना है कि डाकबंगले के भवन में वर्ष 2016 से स्थापित तहसील का कार्य हो रहा है जो अवस्थाओं का शिकार है उन्होंने तहसील कार्यालय को नए भवन में तत्काल स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। जिससे आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और कार्य व्यवस्था भी सुचारु हो सके। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर कुछ औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी बाकी हैं, जिसके चलते शिफ्टिंग में विलंब हो रहा है। हालांकि अधिकारियों की ओर से जल्द ही तहसील कार्यालय को नए भवन में स्थानांतरित किए जाने की बात कही जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस दिशा में कब तक ठोस कदम उठाता है और लोगों को अस्थायी व्यवस्था से निजात मिल पाती है।

# गर्मी में चाय पीने से क्या होता है? अगर जान लिया तो आज से ही पीना छोड़ देंगे!

अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो ये लेख आपको आखिर तक पढ़ना चाहिए। यहां हम आपको बताएंगे इससे क्या नुकसान हैं।

भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुकी है। सुबह की शुरुआत हो या दिनभर की थकान दूर करनी हो, चाय हर मौके पर साथ देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में जरूरत से ज्यादा चाय पीना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है?

अक्सर लोग दिन में कई बार चाय पीते हैं, बिना यह सोचे कि इसका शरीर पर क्या असर हो रहा है। चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन जैसे तत्व अगर अधिक मात्रा में शरीर में जाएं तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। खासकर खाली पेट चाय पीना और बार-बार चाय का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि चाय पीने की सही मात्रा क्या होनी चाहिए और इसके ज्यादा सेवन से कौन-कौन सी समस्याएं हो सकती हैं।

### गैस और एसिडिटी

ज्यादा मात्रा में चाय पीने से पेट में एसिड का स्तर बढ़ जाता है। खासकर खाली पेट चाय पीना इस समस्या को और बढ़ा देता है। इससे सीने में जलन, खट्टी डकारें, पेट फूलना और भारीपन महसूस होता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर पाचन तंत्र भी कमजोर हो सकता है और गैस-अपच की समस्या बार-बार होने लगती है।

### नींद में बाधा

चाय में मौजूद कैफीन दिमाग को उत्तेजित करता है, जिससे नींद पर असर पड़ता है। अगर आप शाम या रात के समय ज्यादा चाय पीते हैं, तो सोने में दिक्कत, बार-बार नींद टूटना और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता और थकान बनी रहती है।

### आयरन की कमी

चाय में टैनिन नामक तत्व होता है, जो शरीर में आयरन के अवशोषण को रोकता है। अगर आप भोजन के तुरंत बाद चाय पीते हैं, तो शरीर जरूरी आयरन को सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता। लंबे समय तक ऐसा करने से एनीमिया, कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

### दिल की धड़कन तेज होना

अधिक मात्रा में कैफीन लेने से दिल की धड़कन तेज हो सकती है। इससे घबराहट, बेचैनी और कभी-कभी हल्का चक्कर भी महसूस हो सकता है। जिन लोगों को पहले से दिल से जुड़ी समस्या है, उन्हें ज्यादा चाय पीने से खासतौर पर बचना चाहिए।

चाय का अधिक सेवन शरीर में पानी की कमी पैदा कर सकता है क्योंकि इसमें हल्का मूत्रवर्धक प्रभाव होता है। बार-बार पेशाब आने से शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे कमजोरी, सूखापन और थकान महसूस हो सकती है। इसलिए चाय के साथ पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।

# महिलाओं में पीसीओएस के हो सकते हैं ये 5 संकेत, न करें नजरअंदाज

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) एक ऐसी स्थिति है, जिससे किसी भी उम्र की महिलाओं को प्रभावित किया जा सकता है। यह समस्या हार्मोनल असंतुलन के कारण होती है और इससे शरीर में पुरुष हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप अंडाशय में कई छोटे-छोटे सिस्ट बनने लगते हैं। आइए आज हम आपको पीसीओएस के कुछ शारीरिक संकेतों के बारे में बताते हैं, जो महिलाओं को नजरअंदाज नहीं करने चाहिए।

### अनियमित या बंद पीरियड्स आना

पीसीओएस का सबसे आम शारीरिक संकेत है मासिक धर्म का अनियमित या अचानक बंद होना। इस समस्या से पीड़ति महिलाओं में मासिक धर्म का अंतराल 2 से 3 महीने तक हो सकता है, जबकि सामान्य महिलाओं में हर महीने मासिक धर्म होता है। कभी-कभी क्कष्टहर् से ग्रस्त महिलाओं में 6 महीने के बाद भी मासिक धर्म नहीं आता है। यह समस्या हार्मोनल असंतुलन के बड़ा कारण होती है।

### वजन का बढ़ना

पीसीओएस से ग्रस्त महिलाओं का वजन बढ़ना भी एक आम संकेत है। इस समस्या के कारण शरीर में पुरुष हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे चर्बी का जमाव होता है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है। यह समस्या महिलाओं के लिए स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसे ठीक करने के लिए संतुलित डाइट करें, रोज़ाना 30-40 मिनट एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद और स्ट्रेस कंट्रोल करें।

### मुंहासे होना

पीसीओएस का एक और शारीरिक संकेत है मुंहासे होना। इससे प्रभावित महिलाओं के चेहरे, ठुड्डी और गालों पर बड़े और दर्दनाक मुंहासे हो सकते हैं। इसके अलावा, सीने, पीठ और कंधों पर भी मुंहासे हो सकते हैं। यह समस्या शरीर में हार्मोनल असंतुलन के कारण होती है। इसे ठीक करने के लिए ऑयल-फ्री स्किनकेयर अपनाएं ज्यादा शुगर और जंक फूड से बचें नियमित एक्सरसाइज करें जरूरत पड़े तो डॉक्टर से दवा लें

### अनिद्रा की समस्या होना

पीसीओएस एक ऐसी समस्या है, जो महिलाओं की नींद को प्रभावित कर सकती है। इससे ग्रस्त महिलाओं को सोने में दिक्कत हो सकती है और वे सोते समय बार-बार जाग सकती हैं। यह समस्या शरीर में हार्मोनल असंतुलन के कारण होती है, जिससे नींद पर भी प्रभाव पड़ता है। इस ठीक करने के लिए आप संतुलित डाइट करें, रोज़ाना 30-40 मिनट एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद लें और स्ट्रेस कंट्रोल करें।

### अनचाही गर्भावस्था होना

पीसीओएस से ग्रस्त महिलाओं में अनचाही गर्भावस्था होने की संभावना ज्यादा होती है। इस समस्या में गर्भावस्था के दौरान गर्भपात होने की संभावना भी अधिक होती है। इसके अलावा, गर्भावस्था के दौरान जच्चा और शिशु की मौत होने का खतरा भी ज्यादा होता है। समय से पहले प्रसव होने का खतरा भी अधिक होता है, जो महिलाओं के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि, यह दवाइयों से सही हो जाता है।

# पांच कॉमन बीमारियां जिनका अब तक डॉक्टरों के पास नहीं है कोई इलाज, हर साल लाखों लोग होते हैं शिकार

एक समय जो बीमारियां मौत का दूसरा नाम मानी जाती थीं, आज उनका इलाज संभव हो गया है। एचआईवी जैसी गंभीर बीमारी को अब दवाओं के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। पर अब भी कई आम समस्याओं का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है।

मेडिकल साइंस में हुई प्रगति और अत्याधुनिक खोजों ने कई गंभीर बीमारियों के इलाज को अब काफी आसान बना दिया है। एक समय जो बीमारियां मौत का दूसरा नाम मानी जाती थीं, आज उनका इलाज संभव हो गया है। एचआईवी जैसे संक्रमण को अब दवाओं के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं कैंसर के इलाज में हुई प्रगति ने लोगों का सर्वाइवल रेट बढ़ा दिया है।

कोरोना महामारी के दौरान हमने वैज्ञानिकों का अद्भुत करिश्मा भी देखा जिसमें तेजी से वैक्सीन तैयार कर लोगों को जानलेवा बनती जा रही कोविड-19 बीमारी से बचाया गया। वैज्ञानिकों की टीम लगातार क्रॉनिक बीमारियों के इलाज को और आसान और किफायती बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

एक समय में कैंसर और एचआईवी जैसी लाइलाज मानी जा रही बीमारियों का अब आसानी से इलाज हो रहा है, पर क्या आप जानते हैं कि आज भी कई ऐसी आम और तेजी से फैलने वाली बीमारियां हैं जो हैं तो बहुत कॉमन लेकिन इनका अब तक कोई खास इलाज मौजूद नहीं है।

### अब भी कई बीमारियों का नहीं है कोई इलाज

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कई बहुत आम सी स्वास्थ्य समस्याओं का अब तक कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर इन बीमारियों के लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए ही दवाइयां देते हैं। बीमारी को जड़ से खत्म करने का तरीका अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसी कई बीमारियों का नाम सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आइए ऐसी ही बीमारियों के बारे में आगे विस्तार से समझते हैं।

### डेंगू का अब तक नहीं है कोई इलाज

क्या आपको पता है कि अब तक डेंगू का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर केवल इसके लक्षणों जैसे बुखार, दर्द और प्लेटलेट्स में गिरावट की समस्या को ठीक करने के लिए दवा देते हैं।

डेंगू एक वायरल संक्रमण है, जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है।

इस बीमारी में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है।

इसके इलाज में मुख्य रूप से खूब पानी पीते रहने, पैरासिटामोल और पौष्टिक चीजों के सेवन की सलाह दी जाती है।

### चिकनगुनिया का भी नहीं है उपचार

डेंगू की ही तरह चिकनगुनिया का भी कोई निश्चित इलाज उपलब्ध नहीं है।

चिकनगुनिया भी एक वायरल बीमारी है, जो मच्छरों के जरिए फैलती है। इसमें तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होता है।

इसके इलाज में केवल दर्द निवारक दवाएं, आराम करने की सलाह दी जाती है।

इससे बचाव को लिए कोई खास दवा या वैक्सीन अब तक नहीं है।

### रेबीज में मौत पक्की

रेबीज एक बेहद खतरनाक वायरल बीमारी है, जो संक्रमित कुत्ते और कुछ अन्य जानवरों के काटने से फैलती है। खास बात यह है कि लक्षण दिखने के बाद इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ये 100% जानलेवा मानी जाती है।

रेबीज के कारण शुरुआत में बुखार, सिरदर्द और कमजोरी होती है। लेकिन बाद में यह दिमाग को प्रभावित करती है, जिससे मरीज को पानी से डर लगने लगता है।

रेबीज का एकमात्र बचाव समय पर वैक्सीन लगवाना है। अगर काटने के तुरंत बाद टीका लग जाए, तो बीमारी को रोका जा सकता है।

### अल्जाइमर को नहीं किया जा सकता है ठीक

अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें धीरे-धीरे याददाश्त और सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है।

यह 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों में ज्यादा देखी जाती है। इसका भी कोई स्थाई इलाज नहीं है।

अल्जाइमर रोग में दिमाग की कोशिकाएं धीरे-धीरे नष्ट होती जाती हैं।

इसमें केवल लक्षणों को धीमा करने में मदद करने वाली दवाएं दी जाती हैं। बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता।

### मल्टीपल स्क्लेरोसिस की समस्या

मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही नर्वस सिस्टम पर हमला करने लगता है।

इससे दिमाग और रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है।

इस बीमारी के कारण कमजोरी, संतुलन बिगड़ने, नजर की समस्या और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

कुछ दवाएं इसकी प्रगति को धीमा करने में मदद करती हैं, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता।

# पीएफ कटने की सैलरी लिमिट बढ़कर होगी 30 हजार रुपये, सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव

**नई दिल्ली, एजेंसी।** प्राइवेट नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार जल्द ही प्रोविडेंट फंड कवरेज के लिए तय की गई बेसिक सैलरी लिमिट को भारी मार्जिन से बढ़ाने पर विचार कर रही है। मौजूदा समय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत अनिवार्य पीएफ कटौती के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय है, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 से 30,000 रुपये तक किया जा सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में इस लंबे समय से लटके प्रस्ताव पर अब तेजी से काम शुरू हो गया है, जिससे आने वाले समय में देश के एक बड़े वर्कफोर्स को रिटायरमेंट फंड और सामाजिक सुरक्षा का सीधा लाभ मिल सकेगा।

## क्यों पड़ी इस बड़े बदलाव की जरूरत?

पीएफ लिमिट बढ़ाने के इस बड़े फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल के दिनों में, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, औद्योगिक और प्राइवेट कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। इस सैलरी हाइक के कारण कई कुशल कर्मचारी 15,000 रुपये की सीमा को पार कर गए हैं और तकनीकी रूप से अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे से बाहर होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर समय रहते यह लिमिट नहीं बढ़ाई गई, तो 'यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी' यानी सभी को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा।

## ईएसआईसी की लिमिट भी बढ़ाने की है तैयारी

ईपीएफओ के साथ-साथ सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत भी वेतन सीमा को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। फिलहाल ईएसआईसी के तहत वेतन सीमा 21,000 रुपये प्रति माह है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और नियमों के बेहतर पालन के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी, दोनों योजनाओं की वेतन सीमा को एक समान स्तर पर लाने की योजना है। श्रम मंत्रालय इसके लिए जल्द ही कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा शुरू करने जा रहा है।

## सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी का दिखा असर

आपको बता दें कि ईपीएफओ की सैलरी लिमिट में आखिरी बार बदलाव एक दशक पहले साल 2014 में किया गया था, तब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया था। इस बार लिमिट बढ़ाने की प्रक्रिया में तेजी आने का एक बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट की वह हालिया चेतावनी भी है, जिसमें कोर्ट ने महंगाई और बढ़ती वेतन दरों के हिसाब से इस सीमा को अपडेट करने पर जोर दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि मौजूदा सीमा के कारण वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा से वंचित हो रहा है। हालांकि, लिमिट बढ़ने से नियोक्ताओं (कंपनियों) पर पीएफ योगदान का वित्तीय दबाव काफी बढ़ेगा, इसीलिए सरकार कोई भी औपचारिक प्रस्ताव पेश करने से पहले हर पहलू पर सावधानी से विचार कर रही है।

# सरकार ने एक दिन में 53 .5 लाख एलपीजी सिलेंडर डिलीवर किए, 98 प्रतिशत बुकिंग डिजिटल माध्यम से हुई

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भले ही पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बिना किसी रुकावट के जारी है। एक ही दिन में 53.5 लाख से ज्यादा सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, जिससे नागरिकों को ईंधन की निर्बाध उपलब्धता का भरोसा दिलाया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, बुकिंग के मुकाबले घरेलू एलपीजी की डिलीवरी सामान्य बनी हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 18 अप्रैल, 2026 को 53.5 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर सिलेंडरों की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

सरकार ने घरों तक सप्लाई को प्राथमिकता दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौजूदा संकट के दौरान खाना पकाने का जरूरी ईंधन उपलब्ध रहे। डिजिटल माध्यमों को अपनाने में भी काफी बढ़ोतरी हुई है; लगभग 98 प्रतिशत एलपीजी बुकिंग ऑनलाइन की जा रही हैं, जबकि 93 प्रतिशत से अधिक डिलीवरी अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) के जरिए प्रमाणित की जा रही हैं ताकि सिलेंडरों का गलत इस्तेमाल या हेरफेर रोका जा सके।

सप्लाई के मोर्चे पर, सरकार ने घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी सेगमेंट के लिए 100 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की है।

कमर्शियल एलपीजी के लिए, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, दवा कंपनियों, स्टील, ऑटोमोबाइल और कृषि जैसे जरूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन दिया गया है।

इसके अलावा, प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई दोगुनी कर दी गई है; यह फैसला मार्च महीने में खपत के पिछले पैटर्न के आधार पर लिया गया है।

एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए, केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज जैसी प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे राज्यों को दिए जाने वाले कोयले के आवंटन में बढ़ोतरी करें, ताकि छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं तक इसकी सप्लाई सुनिश्चित हो सके।

राज्यों को यह सलाह भी दी गई है कि वे घरेलू और कमर्शियल, दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करें।

कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ाकर संकट से पहले के स्तर का लगभग 70 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसमें सुधारों से जुड़े आवंटन भी शामिल हैं। मार्च के मध्य से अब तक, 1.67 लाख मीट्रिक टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई की जा चुकी है, जो 19 किलोग्राम वाले 88 लाख से अधिक सिलेंडरों के बराबर है।

इस बीच, ऑटो एलपीजी की मांग में भी तेजी आई है; अप्रैल महीने में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की औसत दैनिक बिक्री में फरवरी के मुकाबले काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार बारीकी से नजर रखे हुए है, और घरेलू बाजारों में स्थिरता बनाए रखते हुए ऊर्जा की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

# निर्यातकों के लिए व्यापार सुगम बनाने के लिए सरकार ने सुधारों की शुरुआत की

व्यापार सुगमता और निर्यातकों के लिए व्यापार सुविधा प्रदान करने की सरकार ने एक बार फिर प्रतिबद्धता दिखाई है। इस क्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के अंतर्गत आने वाली मानक समितियों के कामकाज को सुदृढ़ करने हेतु लक्षित सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। इसका उद्देश्य अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना, शीघ्र अनुमोदन सुनिश्चित करना और पारदर्शिता एवं पूर्वानुमानशीलता को बढ़ाना है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। लागू किए गए सुधारों की श्रृंखला में मानदंड समितियों (एनसी) के कामकाज में एकरूपता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना शामिल है। इनमें निश्चित पाक्षिक चक्र पर बैठकों का संस्थागत निर्धारण, लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता देना, समयबद्ध तरीके से बैठक के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देना और लंबित मामलों और उनकी अवधि की व्यवस्थित निगरानी करना शामिल है। बयान में कहा गया है कि बार-बार होने वाली स्वीकृतियों को कम करने के लिए, बार-बार आने वाले मामलों की पहचान करके उन्हें मानक इनपुट-आउटपुट मानदंडों (एसआईओएन) में परिवर्तित करने के प्रयास भी किए गए हैं। संबंधित मंत्रालयों से समितियों में अतिरिक्त तकनीकी अधिकारियों को मनोनीत करने का अनुरोध किया गया है ताकि क्षेत्रीय विशेषज्ञता को बढ़ाया जा सके और सदस्यों के सीमित समूह पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अलावा, लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत बैठकें नियमित समय पर आयोजित की जा रही हैं और पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मामलों को कालानुक्रमिक क्रम में निपटाया जा रहा है। क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, विभिन्न मंत्रालयों से दस अतिरिक्त तकनीकी सदस्यों को मनोनीत किया गया है, जिससे तकनीकी प्राधिकारियों की कुल संख्या 12 से बढ़कर 22 हो गई है। इससे समितियों की अधिक संख्या में मामलों को बेहतर दक्षता के साथ संभालने की क्षमता मजबूत हुई है।

सुधारों के परिणामस्वरूप बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। जनवरी 2026 से 7 अप्रैल 2026 के बीच, मानक समितियों की कुल 38 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 3,925 मामलों पर विचार किया गया और 1,770 मामलों का निपटारा किया गया, बयान में कहा गया है।

# संकट के वक्त पूल पार्टी कर रही थी ट्रंप की महिला मंत्री, अब गई कुर्सी

**वॉशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिका के श्रम मंत्री के इस्तीफे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मंत्री लोरी चावेज-डेरेमर पर अमेरिका में संकट के वक्त पूल पार्टी करने का आरोप है। वो भी सरकारी पैसों से। इसकी जांच शुरू होने के बाद नैतिकता के आधार पर डेरेमर ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। हाल के दिनों में यह तीसरा मौका है, जब ट्रंप कैबिनेट के किसी सदस्य का इस्तीफा हुआ है। 58 साल की लोरी चावेज को दूसरी बार सरकार में आने के बाद ट्रंप ने श्रम मंत्री के तौर पर अपने कैबिनेट में शामिल किया था।

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक 58 साल की लोरी कदाचार मामलों की जांच के दौरान इस्तीफा देने का फैसला किया है। उनके विभाग के 4 और अफसरों का इस्तीफा हुआ है। सभी पर अमेरिका में शटडाउन के वक्त पूल पार्टी करने का आरोप है।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग का कहना है कि निजी क्षेत्र में काम करने के लिए डेरेमर ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। एक साल में उन्होंने श्रम क्षेत्र के लिए जो किया है, वो काफी उल्लेखनीय है।

## डेरेमर का इस्तीफा क्यों हुआ?

1- न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक शिकायत के आधार पर डेरेमर को लेकर रिपोर्ट की थी। इसके मुताबिक डेरेमर अपने कर्मचारियों पर चिखती-चिल्लाती हैं। इतना ही नहीं, काम के दौरान डेरेमर शराब का भी सेवन करती हैं।

2- डेरेमर पर यह भी आरोप था कि उन्होंने अपने करीबी अफसरों को सरकारी पैसों पर टूर के लिए भेजा, जो कानूनन गलत था। डेरेमर पर पद का दुरुपयोग का आरोप भी लगा। उनके सुरक्षा गार्ड को लेकर भी कई तरह के आरोप लगाए गए।

3- डेरेमर तब सुर्खियों में आईं, जब अक्टूबर 2025 में अमेरिका में शटडाउन की घोषणा हुई। उस वक्त अपने दोस्तों के साथ डेरेमर पूल पार्टी करने चली गईं। इसको लेकर अमेरिका में हंगामा मच गया।

## प्रारंभिक जांच के बाद हुआ इस्तीफा

रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में यह पाया गया कि काम के दौरान डेरेमर अपने दोस्तों के साथ क्लब में शराब पीने जाती थीं। इतना ही नहीं उन पर सरकारी पैसों से टूर करने का आरोप भी सही साबित हुआ। जांच की रिपोर्ट सीनेट को भेज दी गई, जिसके बाद डेरेमर ने इस्तीफा देने का फैसला किया।

# वेनेजुएला में अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन तेज, देशभर में निकाली जा रहीं है रैलियां और मार्च

**काराकास, एजेंसी।** वेनेजुएला में अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ बड़ा आंदोलन तेज हो गया है। देशभर में रैलियां और मार्च निकाले जा रहे हैं, जिनका मकसद अमेरिका से लगे प्रतिबंध हटवाना है। इस अभियान का नेतृत्व नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज कर रहे हैं।

सोमवार को सैन फेलिक्स के सेरो एल गैलो में आयोजित रैली में रोड्रिगेज ने कहा, 'हमें प्रतिबंधों को समाप्त करना होगा।' उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आम सहमति बनाना और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए दबाव बनाना है, और वेनेजुएलावासियों से मतभेदों को भुलाकर साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

यह राष्ट्रीय आंदोलन 19 अप्रैल से शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने की। इसके तहत ज़ुलिया, ताचिरा और अमेजोनास जैसे कई राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि पिछले लगभग 10 वर्षों से लगे प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा असर आम जनता, खासकर बच्चों पर पड़ा है। उनके मुताबिक, इस दौरान पैदा हुए लाखों बच्चों को बुनियादी सुविधाओं और बेहतर जीवन के मौके नहीं मिल पाए। यह अभियान पूरे देश में रैलियों, सभाओं और जनसभाओं के रूप में चल रहा है और इसका समापन 1 मई को राजधानी काराकास में एक बड़ी रैली के साथ होगा।

## अमेरिका ने डेल्सी रोड्रिगेज पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए

इसी बीच, अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में कुछ नरमी भी देखने को मिली है। हाल ही में अमेरिका ने डेल्सी रोड्रिगेज पर लगे कुछ प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिसे उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। वेनेजुएला में यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ा है। सरकार इसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम कदम मान रही है, जबकि अमेरिका के साथ रिश्ते अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं।

# पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी : मानवाधिकार कार्यकर्ता ने ऑपरेशन सिंदूर की जमकर की सराहना

**लंदन, एजेंसी।** पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी से ठीक पहले मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया ने पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लंदन में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से बिना किसी डर के भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और उसे लगता था कि भारत इसका जवाब नहीं देगा। आरिफ अजाकिया ने पहलगाम आतंकी हमले को बेहद भयावह बताते हुए कहा कि यह 'धर्म के नाम पर किया गया आतंकवाद' था। उनका दावा है कि हमले में लोगों को उनकी आस्था के आधार पर निशाना बनाया गया, जो इसे और भी गंभीर बनाता है। उन्होंने पिछले एक साल में भारत की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने साफ संदेश दिया है कि अब आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक, इसी सख्ती का असर रहा कि पूरे साल कोई बड़ा आतंकी हमला देखने को नहीं मिला। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा कि यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी सिर्फ रोका गया है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो यह फिर शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के इस दावे पर कि वह आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अजाकिया ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जिन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, वे खुद पाकिस्तान की ही बनाई हुई संरचनाएं हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का नाम लिया और आरोप लगाया कि यह संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ही देन है।

# उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर जानकारी उजागर, उपग्रह-आधारित खुफिया जानकारी साझा करने पर अमेरिकी रोक

**वॉशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ उत्तर कोरिया से जुड़ी उपग्रह-आधारित खुफिया जानकारी साझा करने पर आंशिक रोक लगा दी है। यह कदम दक्षिण कोरिया के एकीकरण (यूनिफिकेशन) मंत्री चुंग डोंग-यंग द्वारा उत्तर कोरिया की परमाणु सुविधा से संबंधित संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक किए जाने के बाद उठाया गया है। इस घटनाक्रम से दोनों सहयोगी देशों के बीच एक विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि, दक्षिण कोरियाई सेना का कहना है कि इस रोक से उसकी तत्परता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

## कुसोंग क्षेत्र यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं में से एक

वॉशिंगटन ने यह निर्णय तब लिया जब पिछले महीने संसद के एक सत्र के दौरान मंत्री चुंग ने उत्तर कोरिया के कुसोंग क्षेत्र का उल्लेख करते हुए बताया था कि यह देश की यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं में से एक है। उत्तर कोरिया से संबंधित ऐसी जानकारी का सार्वजनिक खुलासा एक दुर्लभ घटना मानी जाती है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने पुष्टि की, यह सच है कि इस महीने की शुरुआत से ही अमेरिका ने उपग्रहों के ज़रिए जुटाई गई उत्तर कोरियाई खुफिया जानकारी के कुछ हिस्सों को साझा करने पर रोक लगा दी है।' अधिकारी ने आगे कहा कि यह रोक उत्तर कोरिया की तकनीक के कुछ हिस्सों से जुड़ी जानकारी से संबंधित है।

## अमेरिकी आपत्ति और मंत्री का स्पष्टीकरण

खबरों के मुताबिक, अमेरिका ने मंत्री चुंग द्वारा इस जानकारी को सार्वजनिक किए जाने पर आपत्ति जताई है। अमेरिका का मानना है कि यह जानकारी वाशिंगटन द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर आधारित थी। एकीकरण मंत्रालय ने पिछले हफ़्ते कहा था कि चुंग ने ये टिप्पणियां 'सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी' के आधार पर की थीं। सोमवार को चुंग ने उन आरोपों पर खेद व्यक्त किया कि उनकी टिप्पणियों से जानकारी लीक हुई है। उन्होंने कहा कि कुसोंग का जिक्र करने का उनका मकसद दक्षिण कोरिया की उत्तर कोरिया नीति को स्पष्ट करना था।

## खुफिया जानकारी साझा करने का महत्व

सहयोगी देश आमतौर पर उत्तर कोरिया की निगरानी से जुड़ी जानकारी जैसे कि मिसाइल लॉन्च गतिविधियां आपस में साझा करते रहे हैं। एक सूत्र के अनुसार, इस आंशिक रोक के बावजूद दक्षिण कोरियाई सेना को अपनी तत्परता बनाए रखने में कोई समस्या नहीं है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान दोनों देशों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह सहयोग उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर नजर रखने में मदद करता है। वर्तमान आंशिक रोक केवल कुछ विशिष्ट तकनीकी जानकारियों तक सीमित है।

## उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम

उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय रहे हैं। मंत्री चुंग के खुलासे ने कुसोंग को एक नई यूरेनियम संवर्धन सुविधा के रूप में उजागर किया। पहले से योंगब्योन और कांगसोन में ऐसी सुविधाओं की रिपोर्टें थीं। यूरेनियम संवर्धन परमाणु हथियार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस तरह की जानकारी का सार्वजनिक होना उत्तर कोरिया के परमाणु प्रसार प्रयासों पर प्रकाश डालता है। योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, प्रतिबंधित जानकारी उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों से संबंधित मानी जा रही है।

# ताकि न हो गड़बड़ी : 'किसी भी परिस्थिति में सीलबंद कमरों को नहीं खोला जाए', मतगणना से पहले ईसी ने दिया निर्देश

**नई दिल्ली, एजेंसी।** चुनाव आयोग ने मंगलवार को केरल के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। वह मतगणना के दिन से पहले किसी भी परिस्थिति में कोई भी स्ट्रांग रूम न खोलें।

केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने कोझिकोड के पेरामब्रा निर्वाचन क्षेत्र में सोमवार को ईवीएम रखने वाले एक स्ट्रांग रूम के खोले जाने की खबरों और पलक्कड़ के नेनमारा निर्वाचन क्षेत्र में एक और स्ट्रांग रूम खोलने की कथित योजनाओं के बाद यह निर्देश जारी किया। यह दोहराया गया है कि किसी भी परिस्थिति में इंडेक्स कार्ड तैयार करने या ENCORE पोर्टल में डेटा सत्यापित करने के उद्देश्य से किसी भी मजबूत कमरे या बिना सील वाले कमरे को खोला या उसमें प्रवेश नहीं किया जाएगा।

केलकर के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, 'चुनावी प्रक्रिया की अखंडता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।' सोमवार को कोझिकोड जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि कोई भी स्ट्रांग रूम नहीं खोला गया था। कलेक्टर स्नेहल कुमार सिंह, जो जिला चुनाव अधिकारी भी हैं। उन्होंने कहा था कि मतदान अभिलेखों के सत्यापन और अद्यतन के लिए उम्मीदवारों के एजेंटों की उपस्थिति में जेडीटी इस्लाम हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बिना सील वाला सामग्री कक्ष खोला गया था।

### 4 मई को नतीजे

अधिकारी ने एक बयान में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी को केंद्रीय पर्यवेक्षकों और उम्मीदवारों के एजेंटों की निगरानी में भवन की पहली मंजिल पर एक सीलबंद मजबूत कमरे में सुरक्षित रूप से रखा गया था और उस कमरे को खोला नहीं गया था। हालांकि, कांग्रेस और पार्टी के नेतृत्व वाले यूडीएफ के नेताओं ने आरोप लगाया था कि यह घटना चुनाव नियमों का उल्लंघन है। राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

# भारत में बदबू फैला रहा पाकिस्तान, भेज रहा गंदा और जहरीला पानी, पंजाब में कई लोग बीमार

**नई दिल्ली, एजेंसी।** फाजिल्का के अरनीवाला क्षेत्र से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां नहरों में आ रहे काले और संदिग्ध पानी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नहरों में बह रहा पानी दूषित और विषैला प्रतीत हो रहा है, जिसके चलते इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। पहले से ही इस इलाके का भूजल पीने योग्य नहीं है।

माना जा रहा है कि पाकिस्तान की और से कसूर जिले की चमड़ा फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी लगातार सतलुज नदी में छोड़ दिया जाता है और यही पानी आगे जाकर भारतीय सीमा में बॉर्डर से सटे गांव की नहरों के पानी को प्रदूषित करता है। इसी इलाके के विधानसभा क्षेत्र बल्लुआणा के गांव कटैहड़ा के लोग पीने वाले साफ पानी के लिए तरस रहे हैं।

### कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ा

नहरों में काला पानी आ रहा है, जिसके कारण वॉटर वर्क्स की सप्लाई बंद करनी पड़ी है। गांव के लोग मजबूर होकर जमीन के हैंडपंपों का पानी पी रहे हैं, जिससे कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जिला फाजिल्का का गांव कटैहड़ा, जो पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता सुरजीत कुमार ज्याणी का पैतृक गांव है, आजकल साफ पीने वाले पानी की समस्या से जूझ रहा है। पंचायत ने लोगों की परेशानी को देखते हुए वाटर वर्क्स में नया बोरवेल जरूर करवाया है और उसी पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन जमीन का पानी पीने योग्य नहीं है। गांव वालों का कहना है कि वाटर वर्क्स की हालत बहुत खराब है। चारदीवारी टूटी हुई है, जिससे पशु अंदर आ जाते हैं और टंकियां गंदगी से भरी हुई हैं। लोगों को मजबूरी में पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है।

### लोग कर रहे RO प्लांट लगाने की मांग

उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि गांव में साफ पानी की व्यवस्था की जाए। वहीं, गांव के सरपंच जगतपाल भाखर और पंचायत सदस्यों द्वारा पानी की समस्या को लेकर बैठक भी की गई। सरपंच ने कहा कि प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पानी की जरूरत को देखते हुए बोर करवाया गया है और उसी का पानी सप्लाई किया जा रहा है। गांव में आरओ प्लांट लगाया जाए, ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके। पंचायत सदस्यों का कहना है कि गंदा पानी पीने से लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने साफ पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन लोग आज भी गंदा और बीमारियां फैलाने वाला पानी पीने को मजबूर हैं।

### 'पाक के गंदे पानी को रोकने का बंदोबस्त नहीं'

वहीं, इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि ये समस्या पंजाब के लिए काफी बड़ी और पुरानी समस्या है और कई बार वो केंद्र सरकार के सामने अलग-अलग बैठकों में इस मुद्दे को उठा चुके हैं ताकि वहां पर डैम बनाया जा सके या पाकिस्तान से आने वाले गंदे पानी को रोकने का कोई बंदोबस्त किया जा सके। मगर केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब की कोई मदद अब तक नहीं की गई है। हरपाल चीमा ने कहा कि लेकिन अब पंजाब सरकार अपने स्तर पर काम शुरू करेगी ताकि जल्द ही बॉर्डर से सटे गांवों के लोगों को इस गंदे पानी की समस्या से निजात मिल सके।

# पुष्पा 2 को पछाड़ दुनिया की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी धुरंधर 2, अब नजर बाहुबली 2 पर

रणवीर सिंह अभिनीत और आदित्य धर की निर्देशित फिल्म धुरंधर : द रिवेंज को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए एक महीना हो गया है। 31वें दिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर एक और मील का पत्थर पार किया है। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने पुष्पा 2: द रूल के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और यह अब तक की दुनियाभर में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी है।

रणवीर और आदित्य की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनने के बाद, धुरंधर 2 ने हर किसी को अपनी राय देने पर मजबूर कर दिया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। धुरंधर 2 ने पुष्पा 2, केजीएफ 2, जवान, पठान, आरआरआर जैसी बड़ी फिल्मों को कड़ी टक्कर दी है। बॉक्स ऑफिस पर एक महीने तक बिना किसी रुकावट के चलने के बाद, धुरंधर 2, जो अब अपने 5वें हफ्ते में है, अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मज़बूत बनाए हुए है और अक्षय कुमार की भूत बंगला को कड़ी टक्कर दे रही है।

सैकनिल्क रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 31वें दिन शाम के शो के दौरान धुरंधर 2 की ऑक्यूपेंसी 35.08त्न रही, जिसने भूत बंगला को कड़ी टक्कर दी। अक्षय कुमार की फिल्म की ऑक्यूपेंसी 38.46त्न थी। रिपोर्ट के मुताबिक, धुरंधर 2 ने 31वें 3,913 शो के लिए 4.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। 31 दिनों के बाद धुरंधर 2 का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1329।31 करोड़ रुपये ग्रॉस और 1110.47 करोड़ रुपये नेट हो गया है।

धुरंधर का यह सीक्वल पहले ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। इसने अपने पहले भाग को पीछे छोड़ दिया है, जो पिछले दिसंबर में रिलीज हुआ था। धुरंधर ने भारत में लगभग 890 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

बॉक्स ऑफिस नए मुकाबले और धुरंधर 2 की मौजूदा गति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसकी कमाई में गिरावट आ सकती है। इसके चौथे हफ्ते की कमाई, 54.70 करोड़ रुपये, इसके तीसरे हफ्ते की कमाई, 110.60 करोड़ रुपये, की लगभग आधी थी। वहीं, यह इसके दूसरे हफ्ते की कमाई 263.65 करोड़ रुपये से भी आधे से ज्यादा कम थी, जो कि फिल्म के शुरुआती हफ्ते की कमाई, 674.17 करोड़ रुपये, का लगभग एक-तिहाई थी।

धुरंधरः द रिवेंज ने अब तक विदेशों में 420 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है, जिससे इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1748.91 करोड़ रुपये हो गया है। आदित्य धर की इस फिल्म ने सुकुमार की तेलुगू गैंगस्टर थ्रिलर फिल्म पुष्पा 2: द रूल (1742 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब यह सिर्फ एस।एस। राजामौली की फिल्म बाहुबली 2: द कंक्लूजन (1788 करोड़ रुपये) और नितेश तिवारी फैमिली स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म दंगल (2090 करोड़ रुपये) से पीछे है।

# साड़ी, बिंदी और खुले बाल सामंथा रूथ प्रभु का देसी लुक छाया, सादगी ने जीता दिल

साउथ की पापुलर एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु बला की खूबसूरत है। हाल ही में उन्होंने ट्रेडिशनल लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिल चुरा लिया। उनका ये अंदाज देखने लायक है।

सामंथा रूथ प्रभु ने इंस्टाग्राम पर आपकी कई फोटोज शेयर की हैं। जिसमें वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आई।

एक्ट्रेस ने पीच कलर की साड़ी पहनी है, साथ ही सिंपल ब्लाउज कैरी किया है। साड़ी में वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं।

उन्होंने अपने इस ट्रेडिशनल लुक को बिंदी और गोल्डन एक्सेसरीज कैरी करके कंप्लीट किया है।

एक्ट्रेस सटल मेकअप और खुले बालों में बेहद ही हसीन लग रही हैं। उनकी ये सादगी फैंस को भा गई।

उन्होंने जमकर अलग-अलग अंदाज में कई पोज दिए हैं। हर एक तस्वीर में उनका खूबसूरती साफ झलक रही है।

सामंथा की ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस एक्ट्रेस की खूबसूरती पर फिदा हो गए है।

यूजर्स अलग-अलग तरह के कमेंट्स कर उनपर प्यार लुटा रहे हैं।

# महावतार नरसिम्हा के बाद पर्दे पर गूजेंगी महावतार परशुराम की गाथा, हो गया ऐलान

सिने प्रेमियों को 'केजीएफ ', 'सालार ' और 'कांतारा ' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले होम्बले फिल्म्स ने आज परशुराम जयंती के अवसर पर फैंस को तोहफा दिया है। महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी किस्त के रूप में फिल्म महावतार परशुराम का पहला पोस्टर और टीजर साझा किया है। बता दें कि भगवान विष्णु के दस अवतारों पर आधारित सात भागों वाले एनिमेटिड महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की यह दूसरी किस्त है। इससे पहले फिल्म महावतार नरसिम्हा काफी पसंद की गई थी।

होम्बले फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया है। इसके जरिए महावतार परशुराम का पहला पोस्टर रिलीज किया गया है। फिल्म का पोस्टर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में रिलीज किया गया है। इससे साफ है कि यह फिल्म पैन इंडिया स्तर पर बनेगी। पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, जब धर्म का पतन होता है, तब परशु (फरसा) उठता है। महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली पेशकश पेश है। इसके अलावा मेकर्स ने टीजर भी पेश किया है।

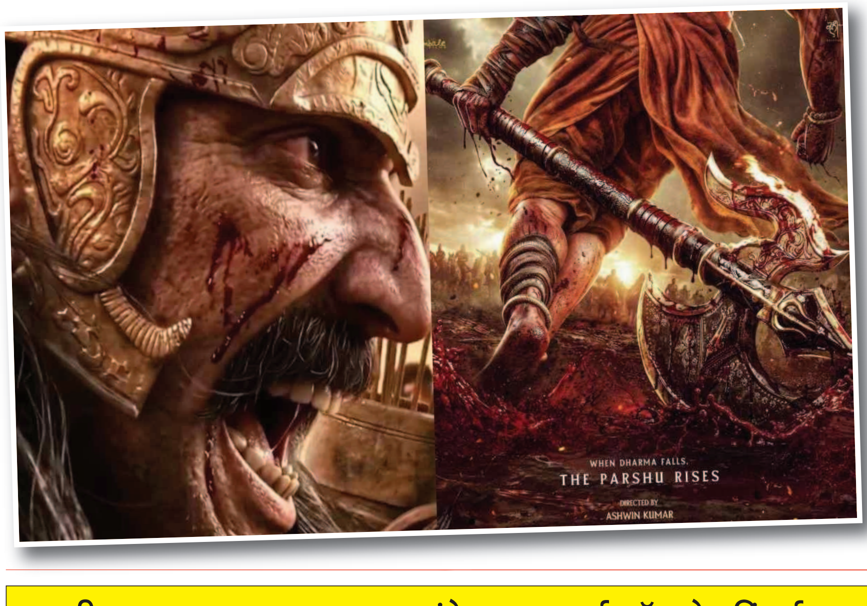


फिल्म महावतार परशुराम का पहला पोस्टर जारी। आगे लिखा है, कोई शासक नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध एक शक्ति; जो युगों-युगों तक संतुलन स्थापित करती है। आपको परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेकर्स की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक यह फिल्म दिसंबर 2027 में यानी अगले साल रिलीज होगी। हालांकि, तारीख को लेकर अभी डिटेल नहीं साझा की गई है।

मेकर्स ने फिल्म की जो पहली झलक साझा की है, वह काफी रोमांचक है। इससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में खास विजुअल स्पेक्टेकल होने की पूरी उम्मीद है। महावतार नरसिम्हा को देखने के बाद से ही फैंस के बीच इसकी अगली फिल्म को लेकर जबर्दस्त उत्साह था। अब मेकर्स ने दूसरी फिल्म का आधिकारिक तौर पर एलान कर दिया है। फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर विजय किरागांदुर ने कहा, हमारी कहानियां ही हमारी ताकत हैं। महावतार परशुराम के साथ हमारा लक्ष्य दर्शकों को अपनी जड़ों की शक्ति से फिर से जोड़ना है और इसे एक ऐसे फॉर्मेट में पेश करना है जो आज की पीढ़ी को पसंद आए। फिल्म का निर्देशन अश्विन कुमार ने किया है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालयः S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website : aryavartkranti.com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्कः 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com